

दैनिक

सद्भावना पाती

...प्राणियों में सद्भावना हो...

www.sadbhawnapaati.com

Email: sadbhawnapaatinews@gmail.com

इंदौर, गुरुवार • 26 सितम्बर, 2024

वर्ष-12 अंक-149

मूल्य -1 रु.

कुल पृष्ठ - 8

संक्षिप्त समाचार

साबरकांठा में ट्रक से टकराई कार, 7 की मौत

- कार के अगले हिस्से को गैस कटर से काटकर शव निकाले, 1 गंभीर

अहमदाबाद (एजेंसी)। गुजरात के साबरकांठा में हिममतनगर हाईवे पर एक इनोवा कार की बुधवार सुबह ट्रक से टकराई गई। हादसे में कार सवार 7 लोगों की मौत हो गई। 1 गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज हिममतनगर सिविल अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने बताया कि कार में सवार सभी 8 लोग अहमदाबाद के रहने वाले थे। वे शामलाजी से अहमदाबाद की ओर जा रहे थे। इसी दौरान इस



कार की ट्रक के पिछले हिस्से से टकराई हुई। हादसा इतना गंभीर था कि कार का बंपर उड़ गया था और शव कार में फंस गए थे। शवों को निकालने के लिए कार की बोर्डिंग को गैस कटर से काटना पड़ा। पुलिस बोली- कार तेज रफतार में थी। एक पटेल ने बताया कि उनकी टीम मीके पर पहुंची तब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी थी। मरने वालों की पहचान धनवानी, चिराग, रविभाई, रोहित, गोविंद, राहुल, रोहित और बर्थ के रूप में हुई है। अभी इनकी उम्र और बाकी डिटेल सामने नहीं है।

योगी मॉडल अपना रही हिमाचल की कांग्रेस सरकार

होटल और ढाबा मालिकों को अब लिखना होगा अपना नाम

शिमला (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी अब हर भोजनालय और फास्ट फूड दुकान के मालिकों को अपनी आईडी लगानी होगी। यह फैसला हिमाचल सरकार ने लोगों की परेशानी को देखते हुए लिया है। इसको लेकर शासन की ओर से शहरी विकास एवं नगर निगम को निर्देश जारी किया गया है। इस बात की जानकारी शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रचारकों से बात करने के दौरान दी। हिमाचल प्रदेश की



सुखरू सरकार को उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल भाग्य है। अब राज्य में सभी भोजनालयों, स्ट्रीट वेंडर्स और खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों के मालिकों को अपनी आईडी बाहर लगानी होगी। इसके साथ ही दुकान पर मालिक का नाम भी लिखना होगा। इस नियम को पूरी तरह से अनिवार्य बनाया गया है। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रचारकों से बात करते हुए कहा कि हमने शहरी विकास और नगर निगम के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि राज्य में स्वच्छ भोजन बेचा जाए।

पं. दीनदयाल जी का दर्शन मानवता की भलाई का मार्ग दिखाता है: सीएम

- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा- देश की बुनियाद से जुड़कर कार्य करने की दी प्रेरणा
- सीएम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें माल्यार्पण कर किया नमन

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा से मानवता का भला करने का दर्शन दिया। उनका मानना था कि देश की जड़ों से जुड़कर हम कार्य करें और अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक का भला करें। शांति के अग्रदूत के रूप में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पं. दीनदयाल उपाध्याय की सोच को क्रियान्वित करते हुए विकास और जनकल्याण के कार्य पूरे देश में जारी है। उनके विचारों को घर-घर तक पहुंचाने के लिए संपूर्ण प्रदेश में अभियान जारी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा लगाए गए जनसंघ के पौधे का



विस्तार विचार के रूप में देश ही नहीं दुनिया के विभिन्न भागों तक हुआ है। जन-कल्याण की कई योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकार देश में अग्रणी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में लाल चाटी स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे।

कांग्रेस आई तो हरियाणा को बर्बाद कर देगी

● पीएम मोदी बोले-कर्नाटक-हिमाचल में ये आपस में लड़ रहे ● कश्मीर में फिर आतंक व अलगाववाद को हवा देना चाहते हैं

सोनीपत (एजेंसी)। हरियाणा चुनाव को लेकर पीएम नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को सोनीपत के गोहाना में रैली की। मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो हरियाणा को बर्बाद कर देगी। कांग्रेस में सिर-फुटौवल्ल मचा हुआ है। कर्नाटक में इनके सीएम और डिप्टी सीएम लड़ रहे हैं। यही हाल हिमाचल और तेलंगाना में है। यहां कांग्रेस को लाने का मतलब हरियाणा के विकास को दांव पर लगाना है। प्रधानमंत्री ने

10 साल पहले पहले सीएम भूपेंद्र हुड्डा की अगुआई वाली कांग्रेस सरकार के वक्त दलितों पर अन्याय का मुद्दा उठाया। इसके अलावा बिना नाम लिए सिस्सा सांसद कुमारी सैलजा के साथ कांग्रेस में हो रहे व्यवहार पर भी सवाल खड़े किए। मोदी ने कहा कि कांग्रेस आतंक और अलगाववाद को हवा देना चाहती है। कांग्रेस को शांति पसंद नहीं, इसलिए जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को वापस लाना चाहती है। पीएम ने



कांग्रेस को भ्रष्टाचार को पालने-पोसने वाली बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार देश में सबसे भ्रष्ट है। कांग्रेस ने जहां कदम रखा, वहां करप्शन और भाई-भतीजावाद पकका है। मोदी ने कहा कि हरियाणा के युवाओं और किसानों का भविष्य बीजेपी सरकार में ही सुरक्षित है। पिछले 10 साल में यहाँ की सरकार पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं हैं। मोदी बोले कि किसानों के फायदे के लिए विदेश से

आयात होने वाले तेल पर टैक्स लगा दिया है। पीएम की यह रैली हरियाणा के जाटलैंड में हुई। जिसे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ माना जाता है। इस इलाके में हर-जीत का फैसला जाट वोटर करते हैं, इसी वजह से भाजपा ने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए उनकी रैली रखवाई थी। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को होने वाली वोटिंग को लेकर यह प्रधानमंत्री की दूसरी रैली थी।

देश के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते

कर्नाटक एचसी के जज के बयान से सीजेआई ने जताई असहमति

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जजों को हिदायत दी कि वे किसी समुदाय पर कमेंट करते वक्त लापरवाही ना बरतें। सीजेआई डीवाय चंद्रचूड़ की बेंच कर्नाटक हाईकोर्ट के जज के विवादित कमेंट का मामला सुन रही थी। जिसमें जज ने बेंगलुरु के एक हिस्से को पाकिस्तान कह दिया था। सीजेआई ने कहा कि आप देश के किसी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते हैं। यह देश की एकता के मौलिक सिद्धांत के खिलाफ है। कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वी श्रीशंकरा के इस कमेंट का वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले की सुनवाई शुरू की। वीडियो के वायरल होने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने बिना परमिशन के कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी थी।



कृषि कानूनों की वापसी वाले बयान पर कंगना की माफी

- बोली-मैं अब सिर्फ कलाकार नहीं, राजनेता भी, मेरी राय पर्सनल नहीं रही, अपने शब्द वापस लेती हूँ

चंडीगढ़ (एजेंसी)। हिमाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद एक्ट्रेस कंगना रनोट ने कृषि कानूनों को लेकर दिए बयान पर माफी मांग ली है। कंगना ने कहा- यदि मैंने अपने बयान से किसी को डिसअपॉइंट किया हो तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। कंगना ने अपने बयान पर सफाई तब दी है जब उनके बयान को लेकर विपक्ष बीजेपी को घेरने में लगा था। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच आए कंगना के बयान से भाजपा ने भी किनारा कर लिया था। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने वीडियो जारी कर कहा था कि कंगना को 3 कृषि कानूनों पर बोलने का हक नहीं है। कंगना ने आज एक्स पर वीडियो जारी कर कहा, बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मस लॉ (कृषि कानून) पर कुछ सवाल किए। और मैंने यह सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए।

बदलापुर की इस घटना को एनकाउंटर मानना मुश्किल

- हाईकोर्ट बोला-रिपोर्ट बताती है गोली सिर पर मारी, सेल्फ डिफेंस में तो पैर पर गोली चलाते हैं

मुंबई (एजेंसी)। ठाणे के बदलापुर में नर्सरी की दो बच्चियों के साथ यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को सवाल उठाए। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा- हम कैसे मान लें कि 4 अफसर एक आरोपी को संभाल नहीं पाए। हथकड़ी भी लगी थी, अपर सेल्फ डिफेंस जैसी स्थिति थी तो आरोपी के पैर पर गोली मारते हैं, सिर में नहीं। बेंच ने कहा- अगर गोली चलाने वाला अफसर असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है, तब वह



यह नहीं कह सकता कि उसे रिपेक्ट कैसे करना है, इसकी जानकारी नहीं थी। उसे पता होना चाहिए कि फायर कहां करना। कोर्ट ने कहा- जैसे ही आरोपी ने ट्रिगर दबाया 4 लोग आसानी से उस पर काबू पा सकते थे।

एमपी के 64,871 बूथों पर बीजेपी की मेगा मंत्रशिप ड्राइव

सीएम ने नरेला में दिलाई सदस्यता, प्रदेश सह प्रभारी ने चूड़ी के ठेले वाले को बनाया मंत्र

भोपाल। भाजपा के संस्थापक पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज बुधवार को एमपी के सभी बूथों पर बीजेपी मेगा मंत्रशिप ड्राइव चला रही है। प्रदेश के सभी 64871 बूथों पर 100-100 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा सहित पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि अलग-अलग बूथों पर आम लोगों को सदस्यता दिलाने पहुंचे। बीजेपी के सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान ठेले पर चूड़ी बेच रहे रेहड़ी वाले को पार्टी की सदस्यता दिलाई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल की नरेला विधानसभा के महामंत्री मंडल के बूथ क्रमांक- 138 व 134 पर लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने हुजूर विधानसभा के गांधी नगर मंडल के बूथ क्रमांक-53 में लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह ने भोपाल उत्तर विधानसभा के गुरुनानक मंडल के बूथ क्रमांक-46 पर सदस्यता दिलाई।



मध्यप्रदेश में अब तक 85 लाख सदस्य बने

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया अब तक मिस्रड कॉल के आधार पर 85 लाख सदस्य बनाए हैं। वहीं, 77 लाख लोग पार्टी के निर्धारित प्रपत्र को भरकर सदस्य बन चुके हैं। अभियान के पहले चरण में हमारा फोकस मास मंत्रशिप पर रहा, लेकिन अब अगले चरण में हम अलग-अलग वर्गों, समूहों के लोगों को पार्टी से जोड़ रहे हैं। वीडी शर्मा ने कहा कि सदस्यता अभियान समाप्त होने के बाद युवा, महिला व किसान समुदाय के कितने लोग भाजपा सदस्य बनें, यह स्पष्ट होगा, लेकिन अभी तक जितनी सदस्यता हुई है, उसमें हर समाज वर्ग के लोग भाजपा से जुड़े हैं। विशेषकर युवा और महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। भाजपा सर्वस्वशी और सर्वव्यापी है के सिद्धांत पर चलकर हर समाज वर्ग को जोड़ने का कार्य करती है। संगठन पर्व में किन्नर समुदाय ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। भाजपा किसान सदस्य दिवस के दिन प्रदेश में बड़ी संख्या में किसानों को पार्टी का सदस्य बनाया है। युवा मोर्चा ने युवाओं को सदस्यता दिलाने का अभियान चलाया, जिसमें एक दिन में 10 लाख सदस्य बनाए। इससे पहले एक दिन में मध्यप्रदेश भाजपा ने 7 लाख 50 हजार सदस्य बनाए थे। मध्यप्रदेश की कुछ ऐसी विधानसभाएं भी हैं, जहां भाजपा के विधायक नहीं हैं।

चीन से 75 फीसदी विवाद खत्म होने पर जयशंकर की सफाई कहा-मेरा बयान सिर्फ सैनिकों के पीछे हटने पर था, बाकी मुद्दों पर चुनौती बरकरार

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ 75 फीसदी विवाद हल होने वाले अपने बयान को लेकर बुधवार को सफाई दी। उन्होंने न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में कहा, मैंने यह बात सिर्फ सैनिकों के पीछे हटने के संदर्भ में कही थी। चीन के साथ दूसरे मुद्दों पर अभी भी चुनौती बनी हुई है। उन्होंने कहा, चीन के साथ भारत का इतिहास मुश्किलों से भरा रहा है। जयशंकर ने कहा, चीन के साथ एलएसी पर हमारा समझौता था लेकिन उन्होंने साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान कई सैनिकों को तैनात कर समझौते का उल्लंघन किया। इसके बाद आशंका थी कि कोई हादसा होगा और ऐसा हुआ भी। झड़प हुई और दोनों तरफ के लोग हताहत हुए।



जयशंकर ने कहा कि चीन के इस फैसले से दोनों तरफ के रिश्ते प्रभावित हुए। अब हम टकराव वाले बिंदुओं पर पीछे हटने के ज्यादातर मामलों को सुलझाने में सक्षम हैं लेकिन गत से जुड़े कुछ मुद्दों को हल करने की जरूरत है। अब अगला कदम तनाव कम करना होगा। 12 सितंबर को जयशंकर ने एक समिट में कहा था, भारत को चीन के साथ सीमा वार्ता में कामयाबी मिली है। लगभग 75 फीसदी विवाद सुलझ गए हैं। सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं का एक-दूसरे के आमने-सामने होना एक बड़ा मुद्दा है। अगर सीमा विवाद का समाधान हो जाता है, तो भारत-चीन संबंधों में सुधार संभव है। जयशंकर ने कहा था कि 2020 में चीन और भारत के बीच झड़प ने दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित किया।

राज्यपाल श्री पटेल ने मुख्य न्यायाधिपति को दिलाई शपथ

- प्रदेश के 28वें मुख्य न्यायाधिपति बने न्यायमूर्ति श्री कैत

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के 28वें मुख्य न्यायाधिपति की शपथ न्यायमूर्ति पुरेश कुमार कैत को दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजभवन के सांदीपनि सभागार में किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राज्यपाल श्री पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने



नव-नियुक्त मुख्य न्यायाधिपति को शपथ ग्रहण के बाद पुष्प-गुच्छ भेंट कर बधाई और शुभकामनाएं दीं। शपथ ग्रहण समारोह का संचालन मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा ने किया।

बीज प्रमाणीकरण विभाग का चपरासी 10 करोड़ के गबन का आरोपी, विभाग के अधिकारी लगे मामले की लीपापोती में: जीतू पटवारी

बीज प्रमाणीकरण विभाग पहले से ही भ्रष्टाचार की चपेट में, विभाग के एमडी और आरोपी चपरासी को बर्खास्त किया जाये: जीतू पटवारी

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि बीज प्रमाणीकरण विभाग में करोड़ों रूपयों का व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किये जाने का मामला पहले ही सामने आ चुका है। अब विभाग के एक चपरासी द्वारा 10 करोड़ रूपयों की एफडी को तुड़वाकर अपने खाते में ट्रांसफर करायें जाने का मामला सामने आया है। संज्ञान में यह बात सामने आयी है कि विभाग का उक्त चपरासी विगत 10 वर्षों से कार्यालय में नौकरी करने ही नहीं जाता, फिर भी उसे पूरा वेतन मिल रहा है, इससे स्पष्ट है कि विभाग के आला अधिकारी इस एफडी कांड में शामिल हैं। श्री पटवारी ने कहा कि मामला राजधानी भोपाल के इमामी गेट के स्थित सेंट्रल बैंक आफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। बीज प्रमाणीकरण विभाग ने इमामी गेट स्थित सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में विगत 30 नवम्बर 2023 को 5-5 करोड़ रूपय की दो एफडी बनवाई थी। जब अधिकारी इन एफडी को तुड़वाने के लिए बैंक पहुंचे तो मामला सामने आया कि इन एफडी की राशि को

चपरासी द्वारा तोड़कर एचडीएफसी बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। इतना ही नहीं एफडी पर मिले 66 लाख रुपये के ब्याज की राशि भी उक्त चपरासी के खाते में ट्रांसफर की गई है। श्री पटवारी ने कहा कि एफडी कांड में चपरासी के साथ बैंक मैनेजर या विभाग के आला-अफसर और एमडी की मिलीभगत तो नहीं है? मामला सामने आते ही बैंक प्रबंधन और प्रशासन ने जांच तो शुरू कर दी, लेकिन सच्चाई अभी भी कुछ और ही बयान कर रही है। वहीं पुलिस ने धोखाधड़ी और गबन के मामले की एफआईआर दर्ज कर ली है लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस फर्जीवाड़े को अंजाम देने में कौन-कौन से अन्य लोग शामिल हैं, इतनी बड़ी राशि का गबन करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन कर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जानी चाहिए। श्री पटवारी ने कहा कि बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा और आंतरिक नियंत्रणों पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। बीज प्रमाणीकरण विभाग के एमडी सहित फर्जीवाड़े में शामिल अन्य अधिकारियों और चपरासी को तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा इस तरह के फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए नई नीतियों और सुरक्षा उपायों पर विचार किया जाना चाहिए। इस मामले ने राज्य सरकार और बैंक प्रशासन इस घटना की गंभीरता से लेते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें।

रतलाम (नप्र)। रतलाम में दो दिन पहले सांड की लड़ाई में घायल हुए बुजुर्ग की बुधवार सुबह मौत हो गई। इसके बाद क्षेत्रवासियों ने नगर निगम के खिलाफ आक्रोश है। रहवासियों ने संत रविदास चौक में बीच सड़क पर शव रख कर चक्काजाम किया। लोग अवैध तबले हटाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि महापौर और अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। हंगामा स्थल पर एसडीएम से लेकर निगम कमिश्नर समेत पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। क्षेत्रवासियों और एसडीएम अनिल भाना में बहस भी हुई। लोगों ने एसडीएम पर गाली-गलौज का भी आरोप लगाया। घटना की गंभीरता को देखते हुए महापौर प्रहलाद पटेल भी पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने महापौर और निगम अफसरों को चूड़ियां दिखाईं। महापौर प्रहलाद पटेल ने परिजनों और रहवासियों से वादा किया है कि अवैध तबलों पर कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल, रविवार को वार्ड 23 के तेजानगर ब्लॉक नंबर 2 निवासी मोहनबाई (75) पति ज्ञानसिंह गुगलिया, उनके बेटा राजेश (55) पर घर के बाहर बैठे थे।



राजेश गुगलिया, मृतक

अचानक सांड लड़ते आए और हमला कर दिया। घटना में मां-बेटे दोनों घायल हो गए। मां को प्राथमिक उपचार कर रविवार को ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया था, जबकि राजेश जिला अस्पताल में भर्ती था। बुधवार सुबह 6 बजे राजेश की मौत हो गई। बताया जाता है कि राजेश को अंदरूनी

चोट लगी थी। मृतक राजेश फेरी लगाकर परिवार का भरण-पोषण करता था। उसकी दो छोटी बहन कविता पति रितेश गोदावत, संगीता पति राजेश मेहता है। बहन कविता ने बताया कि दो दिन तक भाई अस्पताल में भर्ती रहा। किसी अधिकारी ने आकर नहीं पूछा।

नगर निगम आवारा मवेशियों पर ध्यान नहीं देता: राजेश की मौत के बाद क्षेत्रवासियों में नगर निगम के खिलाफ गुस्सा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि वार्ड में लगातार आवारा मवेशी घूमते रहते हैं, लेकिन नगर निगम ध्यान नहीं देता। क्षेत्र के पार्श्व अक्षय संघवी ने बताया कि क्षेत्र के राजेश गुगलिया को दो दिन पूर्व सांड ने हमला कर दिया था। आज सुबह उनका निधन हो गया। शहर में कई अवैध तबले संचालित हो रहे हैं। जिन पर जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। राजेश की शादी नहीं हुई थी। घर में बुजुर्ग माता-पिता का वह इकलौता सहारा था। परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है।

4 महीने पहले एक बुजुर्ग महिला की हुई मौत

इससे पहले भी रतलाम में दो सांडों की लड़ाई में 4 माह पूर्व ही एक बुजुर्ग महिला की मौत हो चुकी है। शुक्रवार शाम टाटा नगर शांताबाई (60) घर के बाहर बाटी संक रही थी। तभी दो सांड लड़ते हुए महिला पर गिर गए।

देश की प्रथम एमएनसीयू का मध्यप्रदेश के विकित्सकीय दल ने किया अध्ययन

● **मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवा को सशक्त करने में काम आयेगा अनुभव**



भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में नवजात शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने तथा प्रसव के उपरांत माताओं और नवजातों की देखभाल और सेवाओं को सशक्त करने के लिए नवीन मदर-न्यू बॉन केयर यूनिट (एमएनसीयू) की स्थापना की जानी है। मध्यप्रदेश के राज्य स्तरीय दल ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में संचालित देश की प्रथम एमएनसीयू इकाई का दौरा किया। अध्ययन भ्रमण से प्राप्त अनुभव मध्यप्रदेश में नवीन एमएनसीयू की स्थापना और संचालन में सहयोगी होगा। संचालक, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य डॉ. अरुणा कुमार, उपसंचालक, शिशु स्वास्थ्य डॉ. हिमानी यादव, हेल्थ स्पेशलिस्ट, यूनिसेफ डॉ. प्रशांत कुमार, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय और डॉ. कैलाश नाथ काटजू (सिविल अस्पताल) के प्रशासनिक अधिकारी, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई के प्रभारी चिकित्सक और नर्सिंग ऑफिसर्स अध्ययन दल में शामिल रहे।

निगम के स्टोर से गायब हुई गुमठी, थाने पहुंचे पार्श्वद

● **कांग्रेसी बोले- भोपाल में गुमठी माफिया सक्रिय ; जांच कर कार्रवाई हो**



भोपाल (नप्र)। भोपाल में नगर निगम के स्टोर से एक गुमठी गायब हो गई। इसे लेकर बुधवार को कांग्रेस पार्श्वद हबीबगंज थाने पहुंच गए। उन्होंने कहा कि भोपाल में गुमठी माफिया सक्रिय है। अब तो निगम के स्टोर से ही गुमठी गायब हो गई है। इस मामले में जांच कर दोषी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। पार्श्वद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान, प्रवीण सक्सेना, जीत सिंह राजपूत, देवाशु कंसाना, अशोक मारण, लक्ष्मण राजपूत ने थाने पर कार्रवाई के लिए आवेदन किया और कार्रवाई की मांग की।

14 महीने पहले जब्त की थी गुमठी

पार्श्वद चौहान ने बताया, कोलार तिराहे पर सचिन रजक की गुमठी थी, जो सिक्ससेलेन सड़क निर्माण के चलते पंचशील नगर में रखी गई थी। 13 जुलाई 2023 को नगर निगम के अमले ने यह गुमठी जब्त कर ली थी। सचिन का कहना था कि जब निगम और जिला प्रशासन विस्थापन की जगह देगा, तब गुमठी छुड़वाकर वापस स्थापित करेगा, लेकिन 20 सितंबर की सुबह एक गुमठी को कुछ लोग ट्रॉले पर रखकर कहीं ले जा रहे थे। यह गुमठी मेरी ही थी। पता चला कि करण नामक व्यक्ति यह गुमठी लेकर जा रहा था। बाद में करण ने बताया, यह गुमठी अरविंद से खरीदी है। इसकी पर्ची भी करण ने सचिन को बताई थी। जब अरविंद का पता लगाया तो वह सीहोर का निक्कला।

स्टोर से ही गायब हो रही गुमठियां

कांग्रेस पार्श्वदों ने बताया कि नगर निगम के अधिकारियों की सांठगांठ से यह गुमठी स्टोर से निकली है। जब गुमठी आखिरी बाहर कैसे आ गई? इसकी जांच की जानी चाहिए।

ग्वालियर में 100वां तानसेन समारोह

पहली बार अन्य राज्यों में भी संगीत कार्यक्रम की तैयारी

भोपाल (नप्र)। ग्वालियर में 14 से 18 दिसंबर के बीच 'तानसेन समारोह-2024' होने जा रहा है। ऐसा पहली बार होगा जब यह मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के मुख्य शहरों में भी इसके लिए संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें मुख्य रूप से दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु, अहमदाबाद, रायपुर, कोलकाता, फतेहपुर सीकरी, नागपुर और मुंबई में भी कई तरह की संगीत प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी।

ग्वालियर में शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में देश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित महोत्सव 'तानसेन समारोह' का यह 100वां वर्ष है। मध्यप्रदेश संस्कृति विभाग के लिए उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत कला अकादमी, मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा यह समारोह आयोजित किया जाता है।

संस्कृति विभाग के अधिकारियों के अनुसार इन शहरों में संबंधित सरकारों से बालचीत की जा रही है, वहां की सरकारों के सहयोग से इस बार तानसेन समारोह में कई तरह के पूर्वर्ण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसमें गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और दिल्ली जैसे राज्य शामिल हैं। इन राज्यों के मुख्य शहरों का शेड्यूल जल्द ही संस्कृति विभाग जारी करेगा। इसके अलावा विदेशी कलाकार भी इस बार समारोह में कई तरह की प्रस्तुतियां देंगे। अभी तक की जानकारी के अनुसार 20 से अधिक देशों के कलाकार यहां प्रस्तुति दे सकते हैं।



तानसेन की जन्म स्थली बेहट

ग्वालियर से लगभग 45 किलोमीटर दूर बेहट ग्राम है, जो तानसेन की जन्मस्थली कही जाती है। संगीत-सम्राट तानसेन की स्मृति में इस स्थान पर भी एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन समारोह के अनुक्रम में किया जाता है।

समारोह में भाग लेने वाले कलाकारों में इच्छुक कलाकार स्थानीय संगीत विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ वहां जाकर संगीत सम्राट के जन्म-स्थान पर अपने श्रद्धा-सुमन अर्पित करते हैं और ग्रामीण जनता को संगीत कला से परिचित कराते हैं। इस आयोजन को सफल बनाने में बेहट ग्राम के निवासियों तथा ग्राम एवं जनपद पंचायत का मूल्यवान सहयोग मिलता

होंगे यह नाट्य प्रदर्शन

संगीत सम्राट तानसेन के जीवन और अवदान पर केंद्रित महानाट्य का प्रदर्शन। नाट्य मध्यप्रदेश नाट्य विद्यालय, भोपाल की तानसेन पर केंद्रित एक विशिष्ट नाट्य प्रस्तुति।

मुख्य समारोह ग्वालियर में ये होगा राष्ट्रीय तानसेन सम्मान अलंकरण दैनिक सांगीतिक सभाएं नाट्य प्रदर्शन संवाद सत्र डाक टिकट का विमोचन पुस्तक/स्मारिकाओं का विमोचन प्रदर्शनी

नर्सिंग के सैकड़ों आदिवासी छात्र छात्राओं ने स्कालरशिप रोकने के विरोध में जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन

धार। नर्सिंग के सैकड़ों छात्रों ने छात्रवृत्ति रोकने के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने मांग की है कि वर्ष 2021 से लेकर 2023 तक की स्कालरशिप और आवास भत्ते पर लगाई गई रोक हटा कर उसका भुगतान शीघ्र किया जाए। छात्रों का आरोप है कि न्यायालय के जिस आदेश का हवाला दिया गया है ऐसा कोई आदेश वास्तव में आया ही नहीं है। आदिमजाति विभाग ने नर्सिंग आदिवासी छात्र छात्राओं की तीन साल से छात्र वृत्ति रोक रखी है जिसके विरोध में सैकड़ों छात्रों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर छात्र वृत्ति देने की मांग की है। छात्रों का आरोप है पड़वंत्र पूर्वक स्कालरशिप पर रोक लगाई गई है। छात्रों का आरोप है की न्यायालय ने कभी भी स्कालरशिप की रोक का कोई आदेश जारी नहीं किया है।बावजूद इसके न्यायालय के आदेश का हवाला देकर छात्रों के हक का हनन किया गया है। सरदार पुर के विधायक प्रताप त्रेवाल ने आरोप लगाया है कि यह छात्रों के खिलाफ साजिश है तो वहीं निजी कालेज के संचालक आशीष चौहान ने कहा कि नर्सिंग के छात्रों की मांग जायज है। एनएसओ के प्रदेश सचिव महेश कुमावत ने कहा कि रोक नहीं हटाई गई तो इसके विरोध में कोर्ट जायेंगे।

लेडी टीचर और टीचर में चलीं सैंडल-चप्पलें, चांटें मारे

मैडम बोलों- वॉशरूम जाते समय वीडियो बनाते हैं; दोनों पर होगी कार्रवाई

ग्वालियर (नप्र)। ग्वालियर में सरकारी स्कूल में टीचर और लेडी टीचर के बीच जमकर चप्पलें चलीं। एक-दूसरे को चांटें मारे। टीचर ने लेडी टीचर को धक्का मारा। वह सीढ़ियों से गिरने से बच गईं। लेडी टीचर का आरोप है कि वॉशरूम जाते समय उनका वीडियो बनाते हैं। लेडी टीचर ने मंगलवार को जनसुनवाई में भी शिकायत की है। जिला शिक्षा अधिकारी अजय कटियार का कहना है कि वीडियो के आधार पर दोनों टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामला सोमवार को अड्डपुरा स्थित मिडिल स्कूल का है। इसका वीडियो मंगलवार को सामने आया। यहां एक ही परिसर में प्राइमरी और मिडिल स्कूल संचालित है। इसमें विद्या रतूड़ी प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं, जबकि शिशुपाल सिंह जादौन मिडिल स्कूल में पढ़ाते हैं। दोनों के बीच किसी बात को लेकर पिछले कई दिन से विवाद चल रहा है।

अभिभावक ने बनाया वीडियो

दरअसल, पेरेंट्स को पता चला था कि स्कूल में टीचर्स लेट आते हैं। इसी सिलसिले में सोमवार को एक बच्चे के पेरेंट्स स्कूल आए थे। आते ही स्कूल में टीचर्स की मौजूदगी देखने के लिए उन्होंने मोबाइल से वीडियो



बनाना शुरू कर दिया। इसी दौरान प्राइमरी स्कूल की टीचर विद्या रतूड़ी क्लास के अंदर गईं।

वहां मौजूद शाला प्रभारी राजीव गौतम को लगा कि विद्या रतूड़ी ने पेरेंट्स को बुलाया है। इसी बात को लेकर अन्य शिक्षक शिशुपाल जादौन भी नाराज

हो गए। उन्होंने गैलरी से लेडी टीचर को धक्का दे दिया। वह गिरते-गिरते बचीं। विरोध करने पर चप्पल से पीटने लगे। चांटें भी मारे। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव भी किया। इसके बाद विद्या रतूड़ी ने भी सैंडल उतार कर शिशुपाल को मारना शुरू कर दिया। गिरेबां पकड़कर चांटें भी मारे। वहां मौजूद अभिभावक ने इसका वीडियो बनाते हुए सोशल मीडिया पर लाइव चला दिया।

टीचर बोलों- हमारे वीडियो बनाते हैं

लेडी टीचर विद्या रतूड़ी का कहना है, 'मुझे स्कूल में परेशान किया जा रहा है। हमें कुछ छात्रों ने बताया है कि जब हम वॉशरूम में जाते हैं, तो बाहर से पुरुष टीचर वीडियो बनाते हैं। स्कूल आने में देर हो जाए, तो नाराजगी जताते हैं। छोटी-छोटी बातों पर बच्चों के सामने अपमान करते हैं। लगातार कुछ मैडम को टारगेट किया जा रहा है।'

जांच के लिए शिक्षा विभाग को सौंपा: सिरोल थाना प्रभारी आलोक सिंह भदौरिया का कहना है कि दोनों पक्षों ने शिकायत की है। पुरुष टीचर ने आरोप लगाया है कि महिला टीचर लेट आती हैं। मामला शिक्षा विभाग का था। दोनों पक्ष पहले संकूल केन्द्र पर भी शिकायत कर चुके हैं। आगे की जांच के लिए शिक्षा विभाग को सौंप दिया है।

एम्बेड कार्यक्रम के तहत डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए चलाया जाएगा जागरूकता अभियान

● स्वास्थ्य विभाग और जीसीपीएल की संयुक्त पहल

भोपाल (नप्र)। मच्छर जनित बीमारियों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए, स्वास्थ्य विभाग ने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (जीसीपीएल) के साथ साझेदारी में जन जागरूकता पहल शुरू की है। यह पहल एम्बेड (मच्छर जनित स्थानिक रोगों का उन्मूलन) कार्यक्रम के अंतर्गत की जा रही है। अभियान का मुख्य उद्देश्य मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और रोकथाम के प्रभावी उपायों को जनता तक पहुंचाना है। उल्लेखनीय है कि गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप वर्ष 2015 से मध्यप्रदेश सरकार के साथ मलेरिया उन्मूलन में सहयोग कर रहा है। जागरूकता अभियान की

शुरुआत भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जैसे चार प्रमुख शहरों में की गई है। अभियान के तहत, मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम, लक्षण पहचान, और समय पर चिकित्सकीय हस्तक्षेप के महत्व पर जोर दिया गया है। एम्बेड कार्यक्रम 2015 में शुरू हुआ था। यह कार्यक्रम 39 जिलों के 27 लाख घरों में संचालित हो रहा है, जिसमें 2 करोड़ 84 लाख लोग शामिल हैं। एम्बेड कार्यक्रम के तहत पिछले 5 वर्षों में मध्यप्रदेश में मलेरिया के मामलों में 89 प्रतिशत की कमी आई है। साथ ही, डेंगू के मामलों में वित्त वर्ष 2023-24 में 65 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

इंदौर, गुरुवार 26 सितम्बर, 2024

यातायात बाधित करने पर 12 डंपरों पर कार्यवाही

इंदौर। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशानुसार इंदौर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। एसडीएम श्रीमती कल्याणी पांडे के नेतृत्व में राजस्व, ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम, खनिज और आरटीओ विभाग के अमले ने नेमावर रोड पर यातायात व्यवधान करने वाले 12 डंपरों पर कार्यवाही की है। गत दिवस नेमावर रोड पर रेत के डंपरों से यातायात व्यवधान को दूर करने के लिए जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों जिसमें राजस्व विभाग, ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम, खनिज विभाग और आरटीओ विभाग के अधिकारियों एवं मैदानी अमले ने संयुक्त दल के माध्यम से ऐसे 12 डंपरों पर कार्यवाही की गई है जो नियत स्थान रती मंडी में ना खड़े होकर रोड पर खड़े पाए गए, जिनके कारण यातायात को बाधित हो रहा था। प्रशासन द्वारा यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं जो निरंतर जारी रहेंगे।

इंदौर आबकारी अमले द्वारा बड़ी मात्रा में अवैध देशी-विदेशी मदिरा जब्त

इंदौर। इंदौर में शराब का अवैध रूप से क्रय-विक्रय, परिवहन तथा भंडारण करने वालों के विरुद्ध कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में आबकारी विभाग के द्वारा अभियान चलाकर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही में बड़ी मात्रा में देशी-विदेशी मदिरा जब्त की गई। सहायक आयुक्त आबकारी मनीष खरे ने बताया कि मुखबिर से प्राप्त सूचना पर आरोपी वृत्त महु अ व महुब के बल द्वारा ग्राम पिगडंबर में 2 अलग-अलग स्थानों पर दबीश दी गई जिसमें विनोद पिता हरनाम ठाकुर निवासी पिगडंबर के घर से 49.5 बल्क लीटर देशी मदिरा व 6.75 बल्क लीटर विदेशी मदिरा, इस प्रकार कुल 56.25 बल्क लीटर मदिरा जब्त की गयी। आरोपी विनोद के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आरोपी आबकारी बल को देखकर मौके से फरार हो गया। एक अन्य प्रकरण में सुगन बाई पति यशवंत निवासी पिगडंबर के घर की तलाशी लेने पर 7.2 बल्क लीटर देशी मदिरा जब्त की गई। आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर मौके पर जमानत देकर छोड़ा गया। इस प्रकार कुल 63.45 बल्क लीटर मदिरा जब्त की गयी। जप्त मदिरा व सामग्री का अनुमानित मूल्य 36 हजार 830 रुपये है।

मिक्षावृत्ति करते हुए पाये जाने पर 12 भिक्षुकों को रेस्क्यू किया गया

इंदौर। भिक्षावृत्ति मुक्त इंदौर अभियान के अंतर्गत प्रशासन द्वारा कठोर कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशानुसार भिक्षुकों को रेस्क्यू किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज खजराना मंदिर चौराहे पर भिक्षावृत्ति करते हुए पाये जाने पर 12 महिला-बच्चों एवं वृद्धों को रेस्क्यू किया गया। उल्लेखनीय है की इसके पूर्व 23 सितंबर को अन्नपूर्णा मंदिर से 10 भिक्षुक एवं 04 बच्चे तथा 24 सितंबर को चिड़ियाघर के सामने बालाजी मंदिर से भी 12 भिक्षुकों को भिक्षावृत्ति करते हुए पाये जाने पर रेस्क्यू किया गया था। उक्त कार्यवाही नगर निगम एवं महिला बाल विकास की संयुक्त टीम द्वारा की जा रही है। संयुक्त टीम के दलों द्वारा आज खजराना मंदिर चौराहे पर 12 महिला- बच्चों एवं वृद्धों को भिक्षावृत्ति करते हुए पाये जाने पर रेस्क्यू किया गया। इंदौर को जिला प्रशासन ने भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए कठोर रवैया अपनाते हुए भिक्षा देने और भिक्षा मांगने दोनों के प्रति कार्यवाही करना प्रारंभ कर दिया है। आगामी दिनों में ऐसी ही कार्यवाही लगातार अन्य चौराहे एवं धर्म स्थलों में जारी रहेगी।

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना :इंदौर जिले के बुजुर्गों को कराई जायेगी अमृतसर की यात्रा

इंदौर से रवाना होगी 21 अक्टूबर को विशेष ट्रेन, सभी खर्च राज्य शासन करेगा वहन

इंदौर। मध्यप्रदेश सरकार की अमृत-मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन- योजना के तहत इंदौर जिले के बुजुर्गों को अमृतसर की यात्रा कराई जायेगी। इसके लिए इंदौर से 21 अक्टूबर को विशेष ट्रेन रवाना होगी। यात्रा का सभी खर्च राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। यात्रा के इच्छुक 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग 11 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इंदौर जिले से 200 यात्रियों को यात्रा करने का लक्ष्य है। आवेदन पत्र इंदौर नगर निगम के झोलल कार्यालयों, जिले के अन्य नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायत कार्यालयों में जमा किये जा सकते हैं। प्रदेश के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो आयकरदाता नहीं हैं और 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के हैं योजना का लाभ ले सकेंगे। यह यात्रा 24 अक्टूबर को पुनः-इंदौर आयेगी।

आयुष्मान योजना बनी वरदान : किडनी से पीड़ित युवती को मिला जीवनदान

इंदौर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई आयुष्मान योजना वरदान बन रही है। इस योजना से जटिल रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क इलाज मिल रहा है। इलाज समय पर मिल जाने पर बीमारों को जीवनदान मिल रहा है। इन्हीं में से एक है इंदौर की युवती जो किडनी में समस्या आ जाने से बेहद परेशान थी। आर्थिक स्थिति कमजोर होने से वह इलाज के बारे में सोच भी नहीं पा रही है। समय पर उसे आयुष्मान योजना की जानकारी मिली। उसने कार्ड बनवाया। उसका इलाज हो गया। उसे नया जीवनदान मिला। इंदौर की युवती ज्योति (परिवर्तित नाम) के किडनी में संकुचन आ गया। डॉक्टरों ने लगभग 8 लाख रुपये का खर्च बताया। खर्च सुनते ही अपने आप को गहरे संकट में महसूस किया। सोचा आर्थिक स्थिति कमजोर है, इलाज कैसे करा पायेंगे। कुछ दिन बीते वह पुनः डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर को अपनी समस्या बताई। इस दौरान उसे आयुष्मान योजना की जानकारी दी गई। उसने प्रक्रिया कर कुछ दिन में ही अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लिया। आयुष्मान कार्ड के आधार पर उसका महंगा इलाज निःशुल्क हो गया। इलाज के दौरान एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। अस्पताल द्वारा दवाईयों के साथ मरीज और अटेंडर परिजन को भोजन भी दिया गया। आज यह युवती और उसके परिजन बेहद खुश है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की यह योजना हमारे लिए वरदान बनी है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति भी आभार व्यक्त किया है। आयुष्मान भारत योजना एक विशाल स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह योजना लाभार्थियों को मुफ्त चिकित्सा बीमा प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से कार्डधारियों को 5 लाख रुपये तक निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलती है।

सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए पहले युवती ने फैलाई अश्लीलता, अब कार्रवाई की मांग उठते देख खेद प्रकट करने के साथ दे डाली सुसाइड की धमकी

इंदौर। शहर में स्थित 56 दुकान चौपाटी और मेघदूत चौपाटी पर एक युवती द्वारा अश्लील और आपत्तिजनक कपड़े पहनकर जनसमूह में वीडियो शूट करने और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। कथित वीडियो के वयरल होते ही हिंदू संगठनों और स्थानीय सामाजिक मंचों ने इसका विरोध

शुरू कर दिया एवं युवती खिलाफ पुलिस द्वारा एक्शन लेने की मांग भी की होने लग गई है विशेष रूप से मां अहिल्या मंच ने इस घटना को -संस्कृति पर धब्बा- करार देते हुए युवती के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सार्वजनिक स्थान पर इस तरह अश्लील कपड़े पहनकर चलने पर हिन्दू संगठन ने आपत्ति ली

और युवती के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही। इसके बाद युवती ने मंगलवार शाम को एक वीडियो जारी किया और कहा कि वह न्यूज में इसलिए है, क्योंकि लोगों का व्यूज की जरूरत है। मुझे इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसे भी उसके वीडियो पर आपत्ति है, वे उससे उसके घर आकर मिल ले। इसके बाद उसने अपना पता भी बताया।

जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह ने धार जिले की दुर्घटना की जांच एवं एफआईआर कराने के निर्देश दिये

प्रभारी छात्रावास अधीक्षक एवं प्रभारी सहायक आयुक्त निलबिबित

इंदौर। धार जिले के सरदारपुर विकासखंड क्षेत्र के शासकीय अनुसूचित जनजाति सौनियर बालक छात्रावास, रिगनाद में बुधवार की सुबह दो छात्रावासी बालकों की करंट लगने से मृत्यु हो गई। जनजातीय कार्य, लोक परिसम्मति प्रबंधन तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने इस दर्दनाक दुर्घटना पर गहन दुःख व्यक्त कर शोक संतप्त परिजन के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त कर मृत बालकों के परिजन को 2-2 लाख रुपये की सहायता राशि मंजूर की है। मृत बालकों के परिजन को जिला रेडक्रॉस से भी सहायता राशि दी गई है। मंत्री डॉ. शाह घटना की जानकारी लेने गुरुवार को रिगनाद (जिला धार) जायेंगे।

जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह ने इस दुर्घटना को संज्ञान में लेकर सूक्ष्मता से जांच कराने एवं एफआईआर कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को घटना के लिये जिम्मेदार

शासकीय सेवकों पर सख्त कार्रवाई करने तथा ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिये सभी छात्रावासों में सुरक्षा के समुचित प्रबंध करने के निर्देश भी दिये हैं। मंत्री डॉ. शाह के निर्देश पर कमिश्नर इंदौर श्री दीपक सिंह द्वारा प्रभारी सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य, जिला धार श्री बृजकांत शुक्ला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

निरीक्षण के लिए हर संभाग में महिला मंडल संयोजक नियुक्त होंगी

जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित सभी छात्रावासों व आश्रम शालाओं का नियमित रूप से निरीक्षण करने के लिये प्रदेश के हर संभाग में एक-एक महिला मंडल संयोजक नियुक्त की जायेंगी, जो 5 दिन अपने-अपने संभाग क्षेत्र के सभी छात्रावासों/आश्रम शालाओं का नियमित रूप से निरीक्षण करेंगी। ये मंडल संयोजक दिन में बालक छात्रावास/आश्रमों का निरीक्षण करेंगी और सप्ताह में 3 दिन अनिवार्य रूप से किसी बालिका छात्रावास/आश्रम में ही रात्रि

विश्राम करेंगी। महिला मंडल संयोजक विद्यार्थियों से चर्चाकर छात्रावास/आश्रम शालाओं में किसी भी प्रकार की व्यवस्थागत कठिनाई, छात्रावास/आश्रम अधीक्षक व अमले का व्यवहार, विद्यार्थियों की पढ़ाई से जुड़ी समस्याएं व उनकी मानसिक परेशानियों/मनोदशा के बारे में भी जानकारी लेंगी। साथ ही विद्यार्थियों की कतिपय प्रकार की समस्याओं का समुचित निदान करने की दिशा में पहल करेंगी, ताकि किसी व्यक्तिगत या व्यवस्थागत समस्या के कारण छात्रावासी विद्यार्थी किसी भी प्रकार का घातक कदम न उठायें।

प्रभारी छात्रावास अधीक्षक निलंबित और बीईओ को शो-काउंट नोटिस दिया

कलेक्टर धार प्रियंक मिश्रा ने शासकीय अनुसूचित जनजाति सौनियर बालक छात्रावास रिगनाद के प्रभारी छात्रावास अधीक्षक बनसिंह कन्नौज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सरदारपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट के मुद्दे पर शहर में निकला विरोध मार्च

● सामाजिक संगठन, हिन्दू संगठनों के साथ कई साधु संत हुए शामिल

इंदौर। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट के मुद्दे पर बुधवार को इंदौर के व्यक्तेश देव स्थान से बड़ा विरोध मार्च निकला गया। जिसमें हजारों की संख्या में साधु संत, सामाजिक संगठन व हिन्दू संगठनों ने भाग लिया। हालांकि निकला गया मार्च शांति से निकाला गया, जिसमें रामानुजाचार्य नागोरिया पीठाधीश्वर स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य महाराज भी शामिल हुए। इंदौर में व्यक्तेश देव स्थान से बुधवार शाम को निकले गए मार्च में बटुक आगे भगवा पताकाएं लेकर चल रहे थे। इसके बाद शामिल लोग हिन्दू समाज का अपमान, न सहेगा हिन्दूस्तान, मिलावट करने वालों को कड़ा दंड मिले जैसे नारे लगाए गए। ज्ञान सौंप कर कहा गया कि दौषियों को चिन्हित कर कठोर दंड दिया जाए और धर्मस्थलों की व्यवस्था में प्रशासनिक दखलतांजी बंद की जाए। हमारी मांग है कि सरकार को धार्मिक देवस्थानों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

शांति मार्च में इतनी भीड़ शामिल हुई कि महानोका, मोती तबेला मार्च का ट्रैफिक रोकना पड़ा। मार्च में वीर बगीची के पवनानंद महाराज, दत्त माडली संस्थान के अण्णा महाराज, अन्नपूर्णा आश्रम के संत जयद्वानंद महाराज, श्री रणजीत हनुमान मंदिर के पंडित दीपेश व्यास, खजराना गणेश मंदिर के पंडित अशोक भट्ट, हंस दास मठ के पवन शर्मा, गजानीन शनि मंदिर के संत दादू महाराज के साथ ही अनेक संत-महंत मौजूद रहे।

श्री गौड मालवीय ब्राह्मण समाज महिला मंडल द्वारा वीर सावरकर नगर में 7 दिवसीय भागवत शुरू

कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाएं शामिल



इंदौर। श्री गौड मालवीय ब्राह्मण समाज महिला मंडल द्वारा आयोजित भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। सात दिवसीय भागवत कथा में विभिन्न आयोजन किए जायेंगे। आयोजन से पूर्व वीर सावरकर नगर से कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में समाज की सैकड़ों महिलाएं समेत समाज के पुरुष वर्ग भी बड़ी संख्या में



उपस्थित रहे। शोभायात्रा में बैंड बाजे घोड़े बगी भी शामिल थीं। भागवत कथा परम पूज्य महाराज मुद्दुल शास्त्री जी के मुखारविंद से श्रद्धालु श्रवण कर सकेंगे। महिला मंडल की अध्यक्ष शोभा मालवीय ने बताया की श्राद्ध पक्ष में भागवत सुनने का विशेष महत्व है इसलिए यह आयोजन श्राद्ध पक्ष में किया जा रहा है। मंडल की सचिव आरती जोशी

ने बताया कि 7 दिवसीय भागवत कथा में महाराज विभिन्न प्रसंगों का व्याख्यान करेंगे। उन्होंने बताया कि गौड ब्राह्मण समाज की नई धर्मशाला का निर्माण किया गया है जिसमें पितरों का आशीर्वाद शामिल है इसलिए इस भागवत में पितृ तर्पण का विशेष आयोजन किया जाएगा। कथा रोजाना दोपहर 2 से 5 बजे तक होगी।

बाद में युवती ने मारा चूटन
शहर में अपने विडियो के कारण विवाद बढ़ता देख बुधवार को युवती ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपने वीडियो के लिए माफ़ी मांगी। उसने कहा कि वह अपनी गलती मानती है और भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं करेगी। युवती ने यह भी कहा कि उसका इरादा किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था। खेद प्रकट करने के साथ सुसाइड की भी बात कही।

बड़ा हादसा टला : वैष्णो देवी जाने वाली मालवा एक्सप्रेस के ब्रेक चिपकने से निकली चिंगारी और धुएं के बाद डरे यात्री

इंदौर। मालवा एक्सप्रेस जो महु से इंदौर होते हुए वैष्णो देवी कटरा (जम्मु) की ओर जाती है। महु से इंदौर के लिए सुबह 11:53 बजे यात्रा शुरू की थी और उसे 12:05 बजे इंदौर स्टेशन पर पहुंचना था। लेकिन 22 मिनट की देरी से, ट्रेन 12:27 बजे इंदौर पहुंची क्योंकि मालवा एक्सप्रेस के पहियों के ब्रेक चिपकने से एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई घटना के दौरान ट्रेन के पहियों से चिंगारी निकलने लगी, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। हालांकि, समय पर धुएं पर काबू पा लिया गया, जिससे कोई बड़ा हादसा टल गया। रेल विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में दौड़ रही होती, तो गंभीर दुर्घटना हो सकती थी। घटना का मुख्य कारण राजेंद्र नगर के पास पहियों का चिपकना बताया गया यात्रियों ने जब देखा कि घ घ कोच के पहियों से चिंगारी निकल रही है, तो उन्होंने तुरंत ट्रेन प्रबंधन को सूचित किया। इसके बाद ट्रेन को राऊ के पास रोकया गया। याई से विशेषज्ञ इंजीनियर पहुंचे और उन्होंने फायर एस्टिंग्विशर की मदद से धुएं पर नियंत्रण पाया। रेल विशेषज्ञ नागेश नामजोशी ने बताया कि यह घटना मटेनेंस में लापरवाही का परिणाम है। उन्होंने कहा कि अगर ट्रेन की गति अधिक होती और एक पहिया रिसॉन्ड नहीं करता, तो कोच पलटने का खतरा उत्पन्न हो सकता था। उन्होंने आगाह किया कि अगर ऐसी घटनाएं बार-बार होती रहीं, तो रेलवे अधिकारियों को इसे गंभीरता से लेना होगा।

इस घटना के बारे में रेलवे पीआरओ खेमराज मीणा ने बताया कि पहिए जाम होने पर स्पार्किंग होती है, जो सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि राऊ के स्टेशन मास्टर ने स्थिति को देखा और ब्रेक को रिलीज करने के बाद ट्रेन को रवाना कर दिया। उनका कहना था कि इसमें कोई लापरवाही नहीं थी और ट्रेन को 10 मिनट से अधिक नहीं रोकया गया।

जिस बीजेपी नेता का मर्डर हुआ, उसकी पत्नी ने किया सुसाइड

इंदौर में फंदे पर मिला शव; कहती थी- मुझे पति के पास जाना है...



कहती थी- मुझे भी मोनू के पास जाना है

मोनु कल्याणे की मौत के बाद दीपिका अवसाद से उबर नहीं पा रही थी। वह कहती थी कि उसे भी मोनु (पति) के पास जाना है। वह बार बार मोनु को याद करती थी। कुछ समय पहले मायके महु में भी रही। तब भी मोनु को लेकर बात-बात पर रोती थी। मोनु की मौत के बाद एक बेटे और बेटी की

जिम्मेदारी भी संभाल रही थी।

मोनु के कमरे में नहीं जाने देते थे

दीपिका को मोनु के कमरे में भी नहीं जाने दिया जाता था। परिवार को पता था कि वह कुछ गलत कर लेगी। इस डर के चलते उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता था। सास हमेशा उसके साथ रहती थी। फिलहाल दीपिका के मायके के लोगों को जानकारी दे दी गई है। सभी महु से इंदौर पहुंच गए हैं। पुलिस को अभी तक किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला। दीपिका के पति मोनु कल्याण इंदौर-3 के पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय के करीबी थे। वे विजयवर्गीय के लिए क्षेत्र का पूरा कामकाज संभालते थे।

23 जून को पति मोनु कल्याणे को मारी थी गोली

दीपि के पति और भाजपा नेता मोनु कल्याणे की 23 जून को 2024 को पीयूष और अर्जुन ने 23 जून को आधी रात 3 बजे गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के घर ढहा दिए थे। दोनों आरोपी अभी जेल में है।

इंदौर में दोपहर में तेज बारिश, उमस भरी गर्मी से राहत

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर में बुधवार सुबह से तेज धूप और उमस के बाद मौसम बदल गया। दोपहर 1.30 बजे बाद इंदौर में तेज बारिश शुरू हो गई और कई इलाकों में अंधेरा छा गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 23 सितंबर से लो प्रेशर एरिया के एक्टिविटी देखने को मिली है। इसके बाद कई स्थानों पर बारिश का दौर शुरू हो जाएगा, जो सितंबर के आखिरी सप्ताह तक बना रहेगा। इसके पूर्व मंगलवार को दिन का तापमान 33.1 (+1) डिग्री और रात का तापमान 23.4 (+3) डिग्री सेल्सियस था। अभी दिन और रात का तापमान औसत से 2 डिग्री ज्यादा होने से काफी गर्मी का एहसास हो रहा है।

इंदौर-उज्जैन में तेज बारिश का अलर्ट- मौसम विभाग ने इंदौर-उज्जैन समेत 31 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। दक्षिणी हिस्से के जिलों जैसे- बैतूल, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, सिवनी और पांडुरंग में भारी बारिश का 'ऑरेंज' अलर्ट है। अगले 24 घंटे में सीहोर, खडवा, झाबुआ, रतलाम, देवास, छिंदवाड़ा, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश हो सकती है। राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, शाजापुर, आगर-मालवा, रीवा, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर जिलों में तेज पानी गिर सकता है। बाकी जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश होने का अनुमान है। इससे पहले मंगलवार को इंदौर, जबलपुर, भोपाल समेत 11 जिलों में बारिश हुई।

संपादकीय

चीन की पैठ से पड़ोसी देश परेशान

भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया के संगठन क्राइड का यह छठवां शिखर सम्मेलन था, जिसमें चारों देशों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। अभी चार वर्ष हुए हैं इस संगठन को बने हुए। इस बीच दो आभासी माध्यम से बैठकें भी हो चुकी हैं। इस सम्मेलन में क्राइड देशों के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। इसमें 'कैसर मूनशाट इनिशिएटिव' के जरिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से जीवन बचाने के लिए साझेदारी और समुद्री सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए 2025 में 'क्राइड एट सी शिप आब्जर्वर मिशन' शुरू करना शामिल है।

इसके जरिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे के समावेशी विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। संभावित बीमारियों और

महामारियों से पार पाने के लिए पहले से रणनीति बनाने पर भी जोर दिया गया है। निस्संदेह ये महत्वपूर्ण समझौते हैं। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से पार पाना इस समय की बड़ी चुनौती है। क्राइड समझौते से निश्चय ही इस पर काबू पाने में काफी मदद मिल सकेगी। इसके अलावा, इस सम्मेलन में क्राइड देशों के बीच सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए किया गया समझौता बेहद अहम है।

हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला और आर्थिक रूप से सक्रिय क्षेत्र है, जिसमें चार महाद्वीप शामिल हैं- एशिया, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और अमेरिका। इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल से सारे देश सतर्क हैं। दरअसल, चीन से मिलने वाली चुनौतियों से पार पाने के मकसद से ही क्राइड का गठन किया गया था। इस क्षेत्र में



भारत की भूमिका अहम है। अमेरिका, आस्ट्रेलिया और जापान चीन का मुकाबला करने के लिए दक्षिण चीन सागर तथा पूर्वी चीन सागर में भारत की उपस्थिति चाहते हैं। भारत भी अपनी सीमाओं और पड़ोसी देशों में चीन की पैठ से परेशान है। अमेरिका से उसकी

तनातनी पुरानी है। ऐसे में, इन देशों के एक मंच पर उपस्थित होने से चीन को चुनौती देने में आसानी होगी। समुद्री सीमा के विस्तार और उसमें इन देशों के साझा सैन्य अभ्यास से चीन को रोकना आसान होगा। इस अर्थ में क्राइड का ताजा शिखर सम्मेलन कई अर्थों में ऐतिहासिक कहा जा सकता है।

फिलहाल देशों की ताकत उनकी तकनीकी संपन्नता से आंकी जाने लगी है। इस मामले में चीन अनेक मामलों में अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया से बहुत आगे है। खासकर सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में फिलहाल पूरी दुनिया में उसका दबदबा है। अमेरिका ने पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में काफी तर्कवी की है, पर अब भी वह चीन से काफी पीछे है। भारत ने सेमीकंडक्टर निर्माण की दिशा में बहुत तेजी से कदम आगे बढ़ाया है, मगर उसके सामने कई

अड़चनें बनी हुई हैं। दो कंपनियों ने इसमें निवेश का उत्साह दिखाया था, मगर उन्होंने अपने कदम वापस खींच लिए। तीसरी कंपनी को विदेशी विशेषज्ञों की जरूरत है, जो फिलहाल उपलब्ध नहीं हो पा रहे। ऐसे में क्राइड सम्मेलन में इस क्षेत्र में शोध और शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए आर्थिक मदद की घोषणा से निश्चय ही उल्लेखनीय नतीजे आने की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि सम्मेलन के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने चीन का नाम लिए बगैर कहा कि क्राइड किसी के खिलाफ नहीं है। हम क्षेत्रीय अखंडता और सभी मुद्दों पर शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करने के समर्थन में हैं। पर इस वास्तविकता से इनकार नहीं किया जा सकता कि क्राइड की सक्रियता से चीन की चिंता तो बढ़ी है।

कलेक्टर आशीष सिंह ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण हेतु प्रश्न बैंक पुस्तिकाओं का विमोचन किया

इंदौर। कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा आज प्रश्न बैंक पुस्तिकाओं का विमोचन किया गया। जिला शिक्षा केन्द्र के द्वारा विद्यार्थियों के लाभ हेतु कठिन अवधारणाओं को सीखने के प्रतिफलों पर आधारित प्रश्न बैंक का निर्माण इंदौर ग्रामीण के विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक हरिओम वैष्णव के मार्गदर्शन, विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक श्रीमती शिल्पी मेहरोत्रा शिवान के निर्देशन एवं सहयोग से किया गया है। प्रश्न बैंक में विज्ञान, गणित की कठिन अवधारणाओं को बच्चों को आसानी से समझाने के लिए विशेष प्रयास किया गया है। प्रश्न बैंक को समस्त विद्यालयों में भेजा जाएगा। विमोचन अवसर पर इंदौर जिला परियोजना समन्वयक श्रीमती शीला मेरावी, जिला अकादमिक समन्वयक विवेक शर्मा, इंदौर ग्रामीण विकासखण्ड समन्वयक हरिओम वैष्णव, शहरी-2 के राजेन्द्र तंवर, प्रश्न बैंक निर्माण की निदेशक श्रीमती शिल्पी मेहरोत्रा शिवान एवं एनएस प्रभारी जितेंद्र राठौड़ उपस्थित थे।

इंदौर जिले में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी की तैयारियां प्रारंभ, पंजीयन कार्य शुरू

इंदौर। राज्य शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार इंदौर जिले में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। इसी सिलसिले में किसानों के पंजीयन का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। पंजीयन किसानों से ही समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी जायेगी। किसानों से आग्रह किया गया कि वे निर्धारित समय अवधि में अपना पंजीयन अवश्य करावा ले। बताया गया कि इंदौर जिले में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी के संबंध में 48 प्राथमिक सहकारी समितियों को पंजीयन केन्द्र बनाया गया है। इन केन्द्रों पर आवश्यक दस्तावेज सहित पहुंचकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। इन केन्द्रों पर पंजीयन निःशुल्क होगा। इसके अलावा एमपी ऑनलाइन, कामन सर्विस सेंटर अथवा लोक सेवा केन्द्र, सायबर कैंफे के माध्यम से भी पंजीयन कराया जा सकता है। किसानों का पंजीयन 20 अक्टूबर तक किया जायेगा। पंजीयन के समय आधार कार्ड, खसरा नकल एवं बैंक पासबुक की प्रति पोर्टल पर अपलोड करना होगी। ?सिकमी/बटाईदार/कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवर सहकारी समिति द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर ही उपलब्ध होगी। एमपी ऑनलाइन, कामन सर्विस सेंटर अथवा लोक सेवा केन्द्र, सायबर कैंफे के माध्यम से पंजीयन कराने पर अधिकतम 50 रुपये का शुल्क रहेगा।

मणिपुर में जातीय हिंसा राज्य और समाज की विफलता

मणिपुर में मैतेई और कुकी के बीच जातीय हिंसा, जो मई 2023 की शुरुआत में भड़की थी, कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस चल रहे संघर्ष में रोजाना झड़पें होती रहती हैं और हाल की रिपोर्ट्स में ड्रोन और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड सहित उन्नत हथियारों के कथित इस्तेमाल पर प्रकाश डाला गया है। 1 सितंबर, 2024 को इफाल पश्चिम के कोत्रक में कुकी उग्रवादियों द्वारा कथित तौर पर किए गए ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन सुरक्षाकर्मियों सहित कई अन्य घायल हो गए।

इसके बाद मणिपुर में कई और ऐसे ही हमले हुए, जिससे पता चलता है कि अत्याधुनिक हथियारों के इस्तेमाल से संघर्ष और बढ़ गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से हिंसा की प्रकृति में आए इस बदलाव ने प्रभावी संघर्ष समाधान की जरूरत को कम कर दिया है। हिंसा के मूल कारणों और सामाजिक प्रतिक्रियाओं को संबोधित करने के बजाय इन हथियारों के स्रोतों की जांच करने पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। मैतेई-कुकी संघर्ष के प्रति राज्य की प्रतिक्रिया काफी हद तक अपर्याप्त रही है। दृष्टिकोण मुख्य रूप से सुरक्षा-केन्द्रित रहा है, जिसमें कर्फ्यू और इंटरनेट निःशुल्क जैसे कानून-व्यवस्था के उपाय हिंसा को रोकने के लिए किए गए हैं। हालांकि ये रणनीतियां परंपरिक हैं, लेकिन वे संघर्ष के अंतर्निहित मुद्दों के बजाय लक्ष्यों को संबोधित करती हैं। 29 जून 2024 को मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के दावों के बावजूद कि संघर्ष जल्द ही हल हो जाएगा, सितंबर में हुई हिंसा में वृद्धि इन आश्वासनों का खंडन करती है। सुरक्षा संबंधी चिंताओं में कथित तौर पर कुकी द्वारा समर्थित म्यांमार से अवैध प्रवास, कुकी-प्रमुख वाले क्षेत्रों में अफीम की खेती और उग्रवादी समूहों को हथियार सप्लाई करने वाले बाहरी तत्व शामिल हैं, सरकारों द्वारा पहचान की गई हैं जिन्हें संबोधित करने के लिए प्राथमिकता दी गई है। हालांकि ये चिंताएं वैध हैं, लेकिन राज्य की प्रतिक्रिया प्रभावी हस्तक्षेप के बिना पहचान तक ही सीमित रही है। मुख्यमंत्री का यह आश्वासन कि संघर्ष समाधान एनडीए-3 सरकार की 100 दिवसीय योजना का हिस्सा था, जो 4 जून को शुरू हुई थी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोगों



ने इसकी घोर विफलता के रूप में आलोचना की है। मणिपुर में नागरिक समाज संगठनों, जैसे कि मणिपुर के स्वदेशी लोगों के विनाश में कथित भूमिका के लिए केन्द्र सरकार की निंदा की है। संघर्ष में शामिल दोनों समुदायों की ओर से प्रतिक्रिया भी कम रही है। शांति बहाल करने के उद्देश्य से सार्थक अंतर-समुदाय संवाद शुरू करने के लिए न्यूनतम प्रयास किए गए हैं। कुकी इन्फो, कुकीज की सर्वोच्च संस्था ने जुलाई 2024 में घोषणा की कि कुकीज और मैतेई के बीच कोई शांति वार्ता नहीं चल रही है। कुकीज की ओर से इस तरह के बयान से पहले सीएम ने बयान दिया था, जिसमें कहा गया था कि मैतेई और कुकीज के बीच शांति वार्ता से मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। हालांकि, 1 अगस्त को जिराबाम जिले में हमार (कुकी उप-समूह) और

मैतेई के बीच शांति बैठक हुई, लेकिन इससे कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। इसके बजाय, दोनों पक्षों के सामुदायिक संगठन अपनी मांगों को लेकर सख्ती से आगे बढ़ रहे हैं। कुकी संगठनों द्वारा अलग क्षेत्रीय आ प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जोर देना उतना ही स्वाभाविक है, जितना कि मैतेई समूहों द्वारा कुकी के विदेशी होने के दावे पर सवाल उठाना। मणिपुर की %क्षेत्रीय अखंडता% को बनाए रखने के मैतेई कथन ने अंतर-समुदाय तनाव को और बढ़ा दिया है। कुकी द्वारा अलग क्षेत्र की मांग को कुकी उप-समूहों के बीच ऐतिहासिक संघर्षों द्वारा चुनौती दी जाती है, जो ऐसी मांग की वैधता को कमजोर करता है। इसके अलावा अप्रैल 2024 में भारत-म्यांमार सीमा पर मुक्त आवागमन व्यवस्था को हटाने के राजनीतिक निर्णय ने तनाव को बढ़ा दिया है। विशेष रूप से इसने कुकी को प्रभावित किया है।

क्या हरियाणा में हुड्डा बनाम सैलजा में थमा गया टकराव?

दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में चुनाव प्रचार पूरे जोर-शोर से चल रहा है लेकिन सत्ता में आने का दावा कर रही मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना दौर रद्द कर दिया। यह तथ्य था कि खड़गे सोमवार को अंबाला और कर्नाल में चुनावी रैलियां करेंगे लेकिन वह दोनों चुनावी रैलियों में नहीं पहुंचे। इसके पीछे भले ही खड़गे के खराब स्वास्थ्य को वजह बताया जा रहा है लेकिन राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा बहुत तेज है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा के बीच चल रही तनातनी और मनमुटाव को वजह से ऐसा हुआ है। खड़गे के चुनावी रैलियों में न आने की वजह से निश्चित रूप से हरियाणा में सियासी चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है। हरियाणा में मतदान की तारीख अब दूर नहीं है। 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और उससे ठीक पहले पार्टी के भीतर भूंपेंद्र हुड्डा बनाम कुमारी सैलजा के बीच संघर्ष की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। यहां याद दिलाना होगा कि सिरसा से लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा 12 सितंबर से पार्टी के चुनाव प्रचार से नदारद हैं। कुमारी सैलजा की नाराजगी की खबरों को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। यहां

तक कहा जाने लगा था कि कुमारी सैलजा कांग्रेस का साथ छोड़ सकती हैं और बीजेपी में जा सकती हैं। लेकिन इस बीच उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। यह मुलाकात रविवार रात को हुई है। कांग्रेस के सूत्रों ने द डेडियन एक्सप्रेस को बताया कि कुमारी सैलजा ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत में कई मुद्दों को उठाया है। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष से कहा है कि किस तरह उन्हें और पार्टी के अन्य नेताओं को पार्टी का घोषणा पत्र बनाने वक्त, उम्मीदवारों के चयन के वक्त नजरअंदाज किया गया है। कुमारी सैलजा ने पार्टी अध्यक्ष को यह भी बताया कि उनके और पार्टी के योग्य कार्यकर्ताओं और नेताओं को पार्टी के मंच से दूर रखा गया है। खड़गे से मुलाकात के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर बताया कि कुमारी सैलजा 26 सितंबर से पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। कुमारी सैलजा के चुनाव प्रचार में नहीं आने से निश्चित रूप से पार्टी के चुनाव अभियान पर अवर पड़ रहा है क्योंकि बीजेपी के नेता भी कुमारी सैलजा के चुनाव अभियान में नहीं पहुंचने का मुद्दा उठा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इसका जवाब देने में सक्षम नहीं हैं कि आखिर कुमारी सैलजा चुनाव प्रचार से दूर क्यों हैं? सैलजा इस बार लोकसभा चुनाव में सिरसा सीट से जीती थीं, इससे



पहले वह अंबाला से सांसद रहने के साथ ही नरसिंहा राव और मनमोहन सिंह की सरकारों में मंत्री रही हैं। वह हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष रहने के साथ ही राज्यसभा की सदस्य भी रह चुकी हैं। खड़गे के चुनावी रैलियों में न आने को बीजेपी ने भी उठाया है। बीजेपी की आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने कहा है कि हुड्डा और सैलजा की गुटबाजी की वजह से कांग्रेस अध्यक्ष को अपना दौर रद्द करना पड़ा है। हरियाणा सरकार के पूर्व गृहमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने भी इस ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि खड़गे का दौरा रद्द होने के बाद कांग्रेस के अंदर चल रहा संघर्ष खुलकर सामने आ गया है। बताया होगा कि कुमारी सैलजा दलित समुदाय से आती हैं और लंबे वक्त से राजनीति में सक्रिय हैं। सैलजा इस बार लोकसभा चुनाव में सिरसा सीट से जीती थीं, इससे

उनमें कांग्रेस के एक नेता के द्वारा जातिगत टिप्पणी करना, कांग्रेस नेतृत्व द्वारा टिकट वितरण में हुड्डा कैप को अहमियत देना और पार्टी के द्वारा विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका नहीं देना भी है। सैलजा और सुरजेवाला विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन केन्द्रीय नेतृत्व ने इसके लिए हमी नहीं भरी। कुमारी सैलजा ने हालांकि न्यूज चैनल आज तक के मंच पर सोमवार को उन्होंने सीएम बनने की तमना को अलविदा नहीं कहा है। कुमारी सैलजा लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद से ही मीडिया चैनलों के साथ बातचीत में सीएम पद को लेकर अपनी दावेदारी टोक चुकी हैं। पार्टी के एक और बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला भी टीवी चैनलों के साथ बातचीत में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने की सूरत में मुख्यमंत्री बनने की खाहिश जाहिर कर चुके हैं। देखा होगा कि पिछले कई दिनों से कांग्रेस के चुनाव प्रचार से किनारा करने वाली कुमारी सैलजा क्या रणदीप सुरजेवाला के दावे के मुताबिक पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। लेकिन हरियाणा के राजनीतिक माहौल और कांग्रेस के भीतर चल रही दिग्गजों की लड़ाई को देखने से यह साफ समझ में आता है कि यह गुटबाजी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है।

आज का कार्टून

गुराल सीईओ सुंदर मिश्राई हुए पीएम मोदी के मुंबई

आप भी भक्त बन गए!!



राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 19 संकुल स्तरीय संगठनों का गठन

इंदौर। इंदौर जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गठित स्व सहायता समूहों के संकुल स्तरीय संगठनों की आम सभा का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिद्धार्थ जैन के मार्गदर्शन में स्व सहायता समूहों के परिसरों के वैधानिक दायित्वों को पूर्ण करने हेतु उक्त साधारण सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जिले में दीनदयाल अन्वयोदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 19 संकुल स्तरीय संगठनों का गठन किया गया है। यह संगठन मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत कराये गये हैं।

संकुल स्तरीय संगठनों द्वारा आयोजित आम सभा में बड़ी संख्या में समूहों सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ बैंकर्स द्वारा भी प्रतिभाग किया जा रहा है। संकुल स्तरीय संगठन की आम सभा में सर्वप्रथम विगत वित्त वर्ष में किये गये

● मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीयन भी कराया गया

● संकुल स्तरीय संगठनों की आम सभाओं के आयोजन का सिलसिला हुआ प्रारंभ

● संगठनों को स्वच्छता गतिविधियों से भी जोड़ा गया

आय व्यय का लेखा जोखा साधारण सभा में समस्त के समक्ष वाचन के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीण आजीविका मिशन के नियमों के तहत अन्य समस्त वैधानिक कार्यवाहियां उपरोक्त साधारण सभा के दौरान की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई लखपति दीदी अभियान के दौरान की गयी कार्यवाही व भविष्य की कार्ययोजना पर भी उपरोक्त साधारण सभा में उपस्थित समस्त के

समक्ष चर्चा की जा रही है। उपरोक्त साधारण सभा में स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधि भी आम सभा में सम्मिलित हुए। साधारण सभा के मंच का उपयोग विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी प्रत्येक समूह तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही हर साधारण सभा में स्वच्छता ही सेवा अभियान अन्तर्गत वृहद स्तर पर स्वच्छता गतिविधियों एवं संवाद का आयोजन किया जा रहा है।

आपकी शिकायत/समस्याओं में

आपका साथी

दैनिक सद्भावना पाती

शिकायत / पत्र संपादक के नाम आप किसी समस्या, शिकायत, मुद्दे, जानकारी, गड़बड़ी, भ्रष्टाचार, नियम विरुद्ध काम आदि की शिकायत संपादक के नाम काट्टसएप पर भेज सकते हैं।

सर्वप्रथम आप अपने मोबाइल में सीएम हेल्पलाइन 181 एप डाउनलोड करें

और उस पर शिकायत उपरान्त हमें उसका स्क्रीन शॉट और फोटो भेजें।

हम उस शिकायत को दैनिक सद्भावना पाती में प्रकाशित करेंगे और आपकी समस्या/शिकायत को रीपट स्वत्म करने का प्रयास करेंगे।

केवल काट्टस एपकरें, कॉल न करें।

केवल काट्टस एपकरें, कॉल न करें। 9685611304

ईमेल आईडी- reporter.spnews@gmail.com

नोट :- जनहित की समस्याओं पर उचित इनाम भी दिया जाएगा।

बैंक में जमा की वृद्धि दर सुस्त, बॉन्ड से 1.3 लाख करोड़ उगाही की योजना

नई दिल्ली, एजेंसी। धीमी जमा वृद्धि से बैंकों को अब दूसरे रास्तों से पैसे जुटाने होंगे। रेटिंग एजेंसी इक्रा का मानना है कि चालू वित्त वर्ष में बैंकों को बॉन्ड जारी करके 1.3 लाख करोड़ रुपये जुटाने होंगे। बॉन्ड के जरिये जुटाई जाने वाली यह रकम अब तक की सबसे ज्यादा रकम होगी। जमा और कर्ज वृद्धि के बीच जारी अंतर को कम करना होगा। इक्रा ने मंगलवार को जारी रिपोर्ट में कहा, लगभग 85 फीसदी बॉन्ड सरकारी बैंक जारी करेंगे। यह बॉन्ड इंधन क्षेत्र के होंगे। तल्लता की विकट स्थिति और कर्ज वृद्धि लगातार जमा वृद्धि से अधिक होने के कारण बैंकों द्वारा वैकल्पिक स्रोतों से धन उगाहना जरूरी हो गया है। बैंकों ने 2023-24 में बॉन्ड से एक लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं। इससे पहले 2022-23 में रिकॉर्ड 1.1 लाख करोड़ रुपये जुटाए थे। बैंकों ने चालू वित्त वर्ष में अब तक बॉन्ड से 76,700 करोड़ रुपये जुटाए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में इसी अवधि के दौरान जुटाई गई रकम से यह काफी ज्यादा है। 30 जून, 2024 तक बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बैंकों की अंतिम राशि 13-14 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। सरकारी बैंकों का इसमें 75 प्रतिशत हिस्सा है। एसबीआई चेरयमैन चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ने कहा, बैंक को उद्योग जगत से चार लाख करोड़ के कर्ज की मांग मिल चुकी है। इससे पता चलता है कि 2024-25 की दूसरी छमाही में निजी क्षेत्र के पूंजीगत खर्च में तेजी आएगी। इक्रा के लिए फंडिंग, सड़कों, नवीकरणीय उर्जा व कुछरिफाइन्सों से आ रही है।

भारत के सबसे बड़े आईपीओ को सेबी की हरी झंडी, अक्टूबर में दे सकता है बाजार में दस्तक



नई दिल्ली, एजेंसी। देश का सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है। सेबी ने हूड्ड मोटर इंडिया के 25,000 करोड़ रुपये के बिक्री प्रस्ताव के ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉसेक्यूटर्स को मंजूरी दे दी है। हूड्ड मोटर के आईपीओ को अक्टूबर में लॉन्च होने की उम्मीद है। हूड्ड का आईपीओ एलआईसी के 2.7 अरब डॉलर की लिस्टिंग का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। हूड्ड मोटर साउथ कोरिया की ऑटोमोबाइल कंपनी है। दूसरी ओर सेबी से हरी झंडी मिलने के बाद स्विंगी को अपने आईपीओ का साइज बढ़ाकर 1.4 अरब डॉलर (लगभग 11,700 करोड़ रुपये) करने की उम्मीद है, जिससे यह देश का 5वां सबसे बड़ा इश्यू बन जाएगा। सूत्रों ने टीओआई से कहा कि स्विंगी को अब सेबी के पास एक अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉसेक्यूटर्स दाखिल करना होगा और ऑफर साइज को बढ़ाने के लिए अक्टूबर के पहले सप्ताह में शेयरधारकों की एक बैठक की योजना बनाई गई है। स्विंगी का आईपीओ अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी जोमैटो के 9,375 करोड़ रुपये के इश्यू से बड़ा होगा जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था।

महंगे लोन से जल्द मिलेगी राहत!

नई दिल्ली, एजेंसी। महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों के लिए अच्छी खबर है। जल्दी ही आपकी लोन की किस्त में कमी आ सकती है। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का ग्रोथ अनुमान 6.8 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। साथ ही उसने उम्मीद जताई है कि आरबीआई अपनी अक्टूबर की मौद्रिक नीति समीक्षा में ब्याज दरों में कटौती शुरू कर देगा। एशिया प्रशांत के आर्थिक परिदृश्य में एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.9 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। इसमें कहा गया कि भारत में ठोस वृद्धि से भारतीय रिजर्व बैंक महंगाई को अपने लक्ष्य के अनुरूप लाने पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा।

10700 फर्जी कंपनियों ने की 10179 करोड़ की कर चोरी, फर्जी पंजीकरण रोकने के लिए अफसर चला रहे दूसरा अभियान

नई दिल्ली, एजेंसी। फर्जी पंजीकरण के खिलाफ जीएसटी अधिकारियों की ओर से देशभर में चलाए जा रहे अभियान में करीब 10,700 फर्जी कंपनियों का पता लगाया है, जिन्होंने 10,179 करोड़ रुपये की कर चोरी की है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के सदस्य शशांक प्रिय ने मंगलवार को कहा, फर्जी पंजीकरण के खिलाफ 16 अगस्त से शुरू हुआ दूसरा अखिल भारतीय अभियान 15 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान में कर अधिकारियों ने 67,970 जीएसटीआईएन (माल एवं सेवा कर पहचान संख्या) की पहचान की है। इनमें से 59 फीसदी या 39,965 जीएसटीआईएन का सत्यापन 22 सितंबर तक हो चुका है।

सीबीआईसी सदस्य ने कहा, इनमें 27 फीसदी ऐसी कंपनियां पाई गई हैं, जो अस्तित्व में ही नहीं हैं। फीसदी के लिहाज से यह संख्या पिछले अभियान की तुलना में करीब समान है। उन्होंने बताया, फर्जी पंजीकरण के खिलाफ पहला अभियान 16 मई से 15 जुलाई, 2023 के बीच चलाया गया था। इसमें जीएसटी पंजीकरण वाली कुल 21,791 ऐसी कंपनियां



पाई गई थीं, जो अस्तित्व में नहीं थीं। इस अभियान में 24,010 करोड़ रुपये की संदिग्ध कर चोरी पकड़ी गई थी।

2,994 करोड़ की आईटीसी रोकी, वसूली 22 करोड़

एसोसिएटेड चैंसर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) के कार्यक्रम में शशांक

प्रिय ने कहा, दूसरे अभियान में 2,994 करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को रोका गया है। साथ ही, 28 करोड़ रुपये की वसूली भी की गई है। उन्होंने कहा, जीएसटी व्यवस्था में बेमेल आंकड़ों की समस्या है। इस कारण 2023-24 में कर अधिकारियों ने 1,12,852 कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। सीबीआईसी अधिकारी ने कहा, प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी

प्रदेश सरकार ओबीसी वर्ग के 50 प्रतिभावान छात्रों को देगी दुनिया के टॉप 100 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई का मौका

राज्य सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग के 50 होनहार छात्रों को विदेश में पढ़ाई का मौका मिलने वाला है। राज्य सरकार द्वारा चयन किये गए इन छात्रों को दुनिया के टॉप 100 विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। सरकार का उद्देश्य ओबीसी वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा के बेहतर वैश्विक शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। आपको बता दें कि चुने गए छात्र विभिन्न शैक्षणिक और प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेकर विदेशों में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इसमें विज्ञान, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मैनेजमेंट और सामाजिक विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शिक्षा शामिल है। इससे छात्रों को न केवल विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, बल्कि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमताओं को और निखारे ताकि वे अपने भविष्य को संवार सकें और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें। सरकार का मानना है कि इन छात्रों को विदेश में पढ़ाई करने का यह

अवसर उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा और वे वापस आकर राज्य और देश के विकास में अहम भूमिका निभा सकेंगे।

राज्य मंत्री ने दी जानकारी

एमपी की पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने कहा है कि भाजपा सरकार ओबीसी समाज को शिक्षित और जागरूक करने के प्रति विशेष रूप से समर्पित है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार, ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए शिक्षा संबंधी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि इस समाज के अधिक से अधिक बच्चों को बेहतर शिक्षा और करियर के अवसर मिल सकें। मंत्री ने आगे बताया कि ओबीसी समाज के होनहार और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए एक नई योजना के तहत, पहले चरण में मध्य प्रदेश के 50 छात्रों को विश्व की शीर्ष 100

विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए विदेश भेजा जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य है कि ओबीसी वर्ग के बच्चे वैश्विक शिक्षा हासिल कर सकें और एक मजबूत करियर बना सकें।

इसके तहत सरकार छात्रों को पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी, योजना के अंतर्गत चयनित छात्रों को शिक्षा के साथ-साथ यात्रा, रहने और अन्य खर्चों के लिए भी सरकार की ओर से सहायता दी जाएगी, ताकि वे बिना किसी आर्थिक चिंता के अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। कृष्णा गौर ने आगे कहा कि यह योजना उन बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं। विदेश में उच्च स्तरीय शिक्षा हासिल करने के बाद ये छात्र न केवल अपने समाज बल्कि राज्य और देश की उन्नति में भी योगदान देंगे, साथ ही राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि इस योजना के तहत विदेश भेजे जाने वाले 50 छात्रों की संख्या को तीन गुना तक बढ़ाया जाए, ताकि अधिक से अधिक छात्रों को इस पहल का लाभ मिल सके।

IIM-Bangalore's MBA programme best in India, 14 Indian institutes get spot in QS Global MBA & Business Master's Rankings 2025

Fourteen Indian full-time MBA programmes have secured a position in the latest Quacquarelli Symonds global list for 2025 released today. IIM Bangalore is the best performer among the Indian institutes, however, it has dropped out of the world's top 50 ranking. The other three Indian MBA programmes that have secured a spot in the top 100 are IIM Ahmedabad, IIM Calcutta, and the Indian School of Business. Moreover, there are three new entries — IIM Kozhikode makes its debut in the 151-200 band, the Institute of Management Technology, Ghaziabad, and Somaiya Vidyavihar University feature in the 251+ band.

Three Indian MBA programmes rank among the world's top 50 for the employability indicator, with a fourth programme securing a spot in the top 100 for this critical indicator. The country's number one management college as per NIRF, IIM Ahmedabad's full-time MBA programme is ranked at the top position nationally in the Entrepreneurship & Alumni Impact category, with two other Indian programmes also ranking among

the global top 100 in this indicator. IIM Bangalore's full-time MBA programme has achieved the highest return on investment in India, with the other two programmes appearing among the world's top 100. IIM-B's full-time MBA programme also leads nationally for the thought leadership of its faculty, with other three programmes appearing among the world's top 100.

Incidentally, none of the 14 ranked Indian MBA programmes features in the world's top 250 for student and faculty diversity, highlighting a significant gender gap in the classroom. While IIMs are encouraging women students, the elite club of IIM-A, Bangalore and Calcutta are still far in bridging the gap. This indicator also assesses the percentage of international students and faculty, an area where Indian business schools continue to lag, underscoring the ongoing challenges in internationalisation within Indian business education, as per QS.

QS CEO Jessica Turner said: "India's performance in the QS Global MBA and Business Master's Rankings 2025

underscores the nation's expanding influence in global business education. Indian institutions are increasingly nurturing leaders prepared to navigate today's complex and dynamic business environments. The strong showing of IIM Bangalore, IIM Ahmedabad, and IIM Calcutta — particularly in employability and alumni impact — demonstrates India's ability to shape top-tier global talent. However, ongoing challenges related to internationalisation and gender diversity remain critical areas for improvement. Bridging these gaps is not only key to enhancing the global competitiveness of India's leading business schools, but also vital for fostering more inclusive environments that align with the future of business leadership."

The United States and the United Kingdom continue to dominate the ranking with the former occupying all three top spots — Stanford GSB's MBA, for the fifth consecutive year, is named the world's number one while The Wharton School remains second, followed by

Harvard Business School in third. Stanford GSB's superiority is underpinned by the world's best alumni impact alongside exceptional Graduate Employability," as per QS.

QS has ranked 60 full-time MBA programmes across Asia, with India emerging as the most represented regional hub. It boasts of 14 ranked programmes which is higher than China. Mainland China follows closely with 10, and Japan rounds out the top three with six programmes. While, IIM Bangalore and IIM Ahmedabad are among the top 10 MBA providers in Asia, IIM Calcutta has dropped just below the top 10 this year. The Indian School of Business maintains a place within the top 15.

The QS Global MBA and Business Master's Rankings 2025 spans 58 countries and territories, analysing the world's 340 best global MBAs and a series of specialised high-demand Business Master's Rankings, including Master's in Management, Finance, Marketing, Business Analytics, and Supply Chain Management.

20 राज्यों में शुरू होगा आधार प्रमाणीकरण

जीएसटी पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणीकरण पहले से ही 12 राज्यों में लागू है। चार अक्टूबर तक अन्य चार राज्य को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इस तरह, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित 20 राज्य आधार प्रमाणीकरण शुरू करेंगे।

खुदरा विक्रेताओं के लिए ई-बिल का डिजाइन ढांचा तैयार

माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के सीईओ मनीष कुमार सिन्हा ने कहा, खुदरा विक्रेताओं के लिए जीएसटी ई-इनवॉयस (बिल) को लागू करने के लिए डिजाइन ढांचा लगभग तैयार है। उद्योग विशेषज्ञ इसकी जांच कर रहे हैं। ई-इनवॉयस बी2बी (कंपनियों के बीच) क्षेत्र में पहले से ही मौजूद है। जीएसटी परिषद की इसी महीने हुई बैठक में प्रायोगिक आधार पर बी2बी (कंपनियों से ग्राहकों तक) क्षेत्र में भी ई-इनवॉयस लागू करने का फैसला किया था। एसोचैम के कार्यक्रम में सिन्हा ने कहा, उद्योग जगत से चर्चा के बाद हम इस बारे में एक दस्तावेज जारी करेंगे कि इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए। साथ ही, जिन व्यवसायों को ई-इनवॉयस जारी करना आवश्यक होगा, उनके लिए सीमा तय करने की प्रक्रिया चल रही है। जीएसटी कानून के तहत एक अक्टूबर, 2020 से 500 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को बी2बी लेनदेन के लिए ई-इनवॉयस अनिवार्य कर दिया गया था। बाद में इसका दायरा बढ़कर पांच करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों तक कर दिया गया।

संभव तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। कर अधिकारी भविष्य में नए कर्दादाओं पर उनके जोखिम 'प्रोफाइल' के आधार पर कुछ पाबंदियां भी लगा पाएंगे। वे एक महीने में कितने बिल जारी कर सकते हैं, हम भविष्य में उसपर भी कुछ पाबंदियां लगा सकते हैं।

अजा-अजजा के युवाओं को दिया जायेगा पीएससी प्री परीक्षा हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण

कक्षाएं 7 अक्टूबर से होंगी प्रारंभ

इंदौर। अनुसूचित जाति-जनजाति के युवाओं को राज्य सेवा परीक्षा 2025 का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके लिए शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तदनुसार कक्षाएं 7 अक्टूबर से प्रारंभ होंगी।

केन्द्र की प्राचार्य डॉ. अलका भार्गव ने बताया कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली राज्य सिविल सेवा प्रारंभिक राज्य सेवा परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले अनुसूचित जाति-जनजाति के युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा। लोक सेवा आयोग द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण की कक्षाएं आगामी 7 अक्टूबर से प्रारंभ होंगी। प्रारंभिक परीक्षा 2025 में निःशुल्क प्रशिक्षण के लिये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र उम्मीदवार ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कार्यालयीन समय में जमा किये जा सकते हैं। आवेदन के साथ 2025 की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने का घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा श्वेतक में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश का मूल निवासी एवं अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग का होना चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र (आय सीमा 6 लाख रुपये), जाति प्रमाण-पत्र तथा मूल निवासी प्रमाण-पत्र लगाने अनिवार्य होंगे। केन्द्र में प्रवेश हेतु न्यूनतम आय सीमा 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर, नवीन विधि महाविद्यालय के सामने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय तक्षशिला परिसर इंदौर में जमा किए जा सकते हैं।

IIT Bhubaneswar faculty is in the world's top 2 percent scientists by Stanford-Elsevier

In a major achievement for the Indian Institute of Technology (IIT) Bhubaneswar, six of its distinguished faculty members have been recognised amongst the top 2% of scientists worldwide, according to the prestigious global ranking released by Stanford University in collaboration with Dutch academic publishing company, Elsevier. This recognition places IIT Bhubaneswar's faculty amongst the most impactful researchers globally, solidifying the institution's reputation for excellence in research and innovation.

THE STANFORD-ELSEVIER RANKING

The Stanford-Elsevier annual ranking is highly regarded in the global academic community and highlights scientists based on the impact of their research, citation index, and other key academic metrics. The ranking evaluates scientists across a range of disciplines, and their placement reflects their career-long research contributions as well as recent breakthroughs. The recognition of six faculty members from IIT

Bhubaneswar underscores the institution's leadership in scientific enquiry and innovation while also showcasing the significant contributions of Indian researchers on the global stage.

RECOGNISED FACULTY MEMBERS

The six IIT Bhubaneswar faculty members who have been included in the 2024 Stanford-Elsevier ranking are:

- Prof. Subhansu Ranjan Samantaray – School of Electrical and Computer Sciences
 - Prof. Rajan Jha – School of Basic Sciences
 - Prof. P. Dinakar – School of Infrastructure
 - Prof. Manas Mohan Mahapatra – School of Mechanical Sciences
 - Dr. Pattabhi Ramaiah Budarapu – School of Mechanical Sciences
 - Dr. Barathram Ramkumar – School of Electrical and Computer Sciences
- These faculty members have been acknowledged for their groundbreaking research and high-impact publications, setting new

benchmarks in their respective fields. Four of these faculty members—Prof. Subhansu Ranjan Samantaray, Prof. Rajan Jha, Prof. P. Dinakar, and Prof. V. R. Pedireddi have also been recognised for their career-long contributions, adding further prestige to their recognition.

SUBJECT-SPECIFIC RECOGNITION

Each of the recognised faculty members has made significant strides in their specific areas of expertise:

- Prof. Subhansu Ranjan Samantaray – Recognised for his pioneering research in the field of energy.
 - Prof. Rajan Jha – Acknowledged for his significant contributions to Optics.
 - Prof. P. Dinakar – Honoured for his expertise in Building and Construction Engineering.
 - Prof. V. R. Pedireddi – Recognised for his outstanding research in Inorganic & Nuclear Chemistry.
- This subject-wise recognition highlights the interdisciplinary nature of research at IIT Bhubaneswar, with

its faculty pushing the boundaries of knowledge across multiple scientific fields.

THE STANFORD-ELSEVIER EVALUATION PROCESS

The comprehensive subject-wise analysis that formed the basis of the Stanford-Elsevier ranking was conducted by a team of scientists from Stanford University and Elsevier BV, a leading scientific publisher. The evaluation classified scientists into 22 primary fields and 174 sub-fields using the Science-Matrix classification, which is widely recognised for its accuracy in reflecting the breadth and depth of academic disciplines.

INSTITUTIONAL PRIDE AND GLOBAL IMPACT

IIT Bhubaneswar's Director, Prof. Shreepad Karmalkar, expressed his pride and congratulations to the recognised faculty members. He stated, "This recognition is a testament to the high-calibre research being conducted at IIT Bhubaneswar. Our faculty members continue to push the boundaries of knowledge and innovation, and their inclusion in this elite list reflects the

institute's commitment to excellence in research and development. We are committed to advancing scientific inquiry and supporting our faculty as they contribute to solving real-world problems through their work."

ACKNOWLEDGING INDIA'S ROLE

The inclusion of six IIT Bhubaneswar faculty members in the Stanford-Elsevier ranking not only celebrates individual achievements but also reinforces India's growing role in global research and development. With this recognition, Indian scientists continue to make their mark on the international stage, contributing to breakthroughs across a wide array of scientific disciplines.

The recognition of IIT Bhubaneswar faculty amongst the top 2% of scientists worldwide underscores the institution's leadership in research, innovation, and academic excellence. As Indian scientists continue to influence global scientific progress, this achievement serves as a milestone, reflecting the growing impact of India's academic community on addressing global challenges and advancing human knowledge.



एग्रीकल्चर के प्रति बदला है युवाओं का नजरिया

देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, वहीं यह सेक्टर पचास फीसद से ज्यादा आबादी को रोजगार भी उपलब्ध कराता है। इसके अलावा हाल के वर्षों में जिस तरह से कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण हुआ है, इसमें नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा है, पारंपरिक खेती के साथ-साथ ऑर्गेनिक और इनोवेटिव फार्मिंग हो रही है, उसने एग्रीकल्चर के प्रति समाज और खासकर युवाओं का नजरिया काफी हद तक बदला है। यही कारण है कि बीते कुछ समय में आईआईटी और आईआईएम से पास-आउट कई युवाओं ने मल्टीनेशनल कंपनियों की जॉब छोड़कर एग्रीकल्चर और एग्रीबिजनेस की ओर रुख किया है। इनके अलावा भी दूसरे सेक्टरों में काम करने वाले युवा हॉर्टिकल्चर, डेयरी, ऑर्गेनिक और पोल्डी फार्मिंग जैसे पेशे से जुड़ रहे हैं। उन्हें गर्व है कि वे देश और किसानों के लिए कुछ सकारात्मक कर पा रहे हैं।

ऑर्गेनिक खेती का जिज्ञासु आजकल बहुत हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी को इसमें करियर बनाना है, तो वह क्या करे। गौरतलब है कि यह ऐसी खेती है, जिसमें सिंथेटिक खाद, कीटनाशक आदि जैसी चीजों के बजाय तमाम ऑर्गेनिक चीजें जैसे गोबर, वर्मी कंपोस्ट, बायोफर्टिलाइजर, क्रॉप रोटेशन तकनीक आदि का इस्तेमाल किया जाता है। कम जमीन में, कम लागत में इस तरीके से पारंपरिक खेती के मुकाबले कहीं ज्यादा उत्पादन होता है। यह तरीका फसलों में जरूरी पोषक तत्वों को संरक्षित रखता है और नुकसानदेह केमिकल्स से दूर रखता है। साथ ही यह पानी भी बचाता है और जमीन को लंबे समय तक उपजाऊ बनाए रखता है। यह पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मददगार है।

कैसे करें शुरुआत?
अगर आपको ऑर्गेनिक खेती शुरू करनी है, तो सबसे पहले आपको इसका प्रोजेक्ट या ब्लू प्रिंट बनाना होगा। यह तय करना होगा कि कितनी जमीन पर यह खेती करेंगे। जमीन की लोकेशन क्या है? जमीन किस फसल के लिए अच्छी है? आपका बजट कितना है? यह प्रोजेक्ट किसी भी चार्टर्ड एकाउंटेंट से बनवा सकते हैं। इसके बाद आपको फॉर्म 1 ए-1, 1 ए-3, 1 जी और फॉर्म 11 भरकर रजिस्ट्रेशन फीस के साथ अपने

राज्य के डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में जमा करना होगा। सरकार देती है सब्सिडी कृषि वैज्ञानिक आपकी जमीन की जांच करेंगे और यह तय करेंगे कि इसकी मिट्टी किस फसल की खेती के लिए अच्छी है। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट कृषि विभाग में पास होने के लिए भेज दिया जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए तकरीबन हर राज्य में सरकार 80 से 90 फीसद तक सब्सिडी देती है। मतलब यह आपको पूरे प्रोजेक्ट में 10 से 20 फीसद ही इनवेस्ट करना होगा। प्रोजेक्ट पास होने के बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग टैक्निक वाली कंपनियां सेटअप लगाने के लिए आपसे खुद संपर्क करती हैं। सरकार से मिले पैसों से ये कंपनियां आपकी जमीन पर ग्रीन हाउस और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सेटअप लगाती हैं। साथ ही आपको ट्रेनिंग भी देती हैं।

पूरे देश में चल रहा प्रोजेक्ट

सरकार की ओर से नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है। इसके सेंटर की वेबसाइट से आप और भी जानकारी ले सकते हैं। दिल्ली स्थित पूसा इंस्टीट्यूट से भी पूरी जानकारी और ट्रेनिंग ले सकते हैं।

सिर्फ मानसून पर निर्भर नहीं कृषि

कृषि अब पूरी तरह से मानसून पर निर्भर नहीं है। वैज्ञानिक तरीके से अगर खेती की जाए, तो फसल भी अच्छी होती है और पानी भी कम लगता है। पहले जैसे सूखे के हालात अब नहीं पैदा होते। अब बारिश के पानी का स्टोरेज भी बेहतर तरीके से किया जाता है। इससे बारिश कम होने पर भी फसलों को पर्याप्त पानी मिल जाता है। एग्रीकल्चर स्वरोजगार का सबसे अच्छा साधन है। इससे अब अच्छी कमाई भी की जा सकती है। बहुत से प्रोफेशनल फार्मर साइंटिफिक फार्मिंग के जरिये न सिर्फ अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। यही नहीं, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टरों में एग्रीकल्चर का स्कोप तेजी से बढ़ रहा है।



ललित कला स्नातक एक स्नातक की डिग्री है जो आपको दृश्य, ललित या प्रदर्शन कला में एक पेशेवर करियर के लिए तैयार करती है। आपका कोर्सवर्क आपके फाइन आर्ट्स मेजर पर निर्भर करता है। कुछ प्रमुख जो आप ललित कला स्नातक के साथ कर सकते हैं उनमें फोटोग्राफी, कला इतिहास और नृत्य शामिल हैं। अधिकांश कार्यक्रमों में रचनात्मक अभ्यास के घंटों के साथ-साथ कक्षा निर्देश शामिल हैं। अंततः, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री आपको कला में विभिन्न प्रकार के करियर विकल्पों के साथ एक अच्छी तरह से शिक्षा प्रदान करती है। मुख्य ललित कलाएं फिल्म, नृत्य, पेंटिंग, फोटोग्राफी, वास्तुकला, मिट्टी के बर्तन, वैचारिक कला, मूर्तिकला, संगीत, प्रिंटमेकिंग, इंटीरियर डिजाइन और नाटक हैं। यह छात्रों को कलाकार बनने और कला के निर्माण से जुड़ी अन्य प्रथाओं का पालन करने के लिए सिखाता है और तैयार करता है। अरस्तू के अनुसार, "कला का मुख्य उद्देश्य चीजों को बाहरी उपस्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करना है, बल्कि उनके आंतरिक महत्व का भी प्रतिनिधित्व करना है"।

पाठ्यक्रम और अवधि

ललित कला पाठ्यक्रमों में बड़ी संख्या में प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम हैं जो विभिन्न संस्थानों द्वारा पेश किए जाते हैं। आप ललित कला में स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रम भी कर सकते हैं। पाठ्यक्रमों की अवधि 1 से 5 वर्ष तक होती है।

डिप्लोमा कोर्स

ललित कला में डिप्लोमा: यह एक वर्षीय पाठ्यक्रम है। यह कोर्स 12वीं के बाद किया जा सकता है। स्नातक के अंतर्गत का पाठ्यक्रम: बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स (बीएफए) या बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स (बीवीए): इस कोर्स की अवधि 4 से 5 साल है। ललित कला में कला स्नातक (बीए): यह तीन साल की अवधि का कार्यक्रम है।

परास्नातक पाठ्यक्रम

मास्टर ऑफ फाइन आर्ट (एमएफए) या मास्टर इन विजुअल आर्ट्स (एमवीए): यह दो साल की अवधि का कार्यक्रम है। ललित कला में मास्टर ऑफ आर्ट्स (एमए): इस पाठ्यक्रम की अवधि आम तौर पर दो वर्ष की होती है। कुछ संस्थान पत्राचार और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से स्नातक पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। दो प्रसिद्ध संस्थान इन्ग्लैंड, दिल्ली और दिल्ली विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग पत्राचार में ललित कला पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।

करियर विकल्पों के साथ अच्छी शिक्षा प्रदान करती है फाइन आर्ट्स की डिग्री

ललित कला में आवश्यक कौशल

आपके द्वारा बनाई गई ड्राइंग आमतौर पर नजर में यथावधि होनी चाहिए। आपको कला सामग्री और उनका उचित उपयोग कैसे करना है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अपने काम की प्रस्तुति और प्रदर्शन उचित तरीके से और सटीक होना चाहिए। आपके पास रचनात्मकता होनी चाहिए। रंग और रंग सिद्धांत के साथ प्रयोग की जाने वाली तकनीकें होनी चाहिए। संचार और पारस्परिक कौशल आपके भीतर मौजूद होनी चाहिए। आपको कुछ नवीनतम तकनीकों के साथ उपयोग किए जाने वाले सभी डिजिटल मीडिया का ज्ञान होना चाहिए।

एडमिशन

आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्च माध्यमिक शिक्षा (12वीं) की परीक्षा पूरी करने के बाद डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कर सकते हैं। आप कुछ बीएफए संस्थानों द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मास्टर प्रोग्राम में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ललित कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त करनी होगी।

कुछ प्रसिद्ध कॉलेज जो ललित कला में यूजी और पीजी पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं:

- हैदराबाद विश्वविद्यालय
- दिल्ली विश्वविद्यालय
- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
- कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय
- एमटी विश्वविद्यालय
- इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स, दिल्ली

करियर और नौकरियां

आज विभिन्न क्षेत्रों में ललित कला के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। उत्कृष्ट वेतन, लोकप्रियता और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, भारत की युवा आबादी इस क्षेत्र में आकर्षित हो रही है। स्नातक पूरा करने के बाद छात्रों के पास एक कला शिक्षक, सरकारी कार्यालयों में कलाकार या फोटोग्राफर के रूप में काम करने का विकल्प होता है। आप एक स्वतंत्र कार्यकर्ता के रूप में भी अपना करियर शुरू कर सकते हैं और निर्देशन, कपड़े, फोटोग्राफी, टेलीविजन

ललित कला स्नातक एक स्नातक की डिग्री है जो आपको दृश्य, ललित या प्रदर्शन कला में एक पेशेवर करियर के लिए तैयार करती है। आपका कोर्सवर्क आपके फाइन आर्ट्स मेजर पर निर्भर करता है। कुछ प्रमुख जो आप ललित कला स्नातक के साथ कर सकते हैं उनमें फोटोग्राफी, कला इतिहास और नृत्य शामिल हैं।

और फैशन के लिए जा सकते हैं।

आप अकादमिक, वास्तुकला और फिल्म उद्योग में भी करियर बना सकते हैं। आप प्रकाशन या कपड़ा उद्योग में पत्रिकाओं, विज्ञापन एजेंसियों और समाचार पत्रों के रचनात्मक विभागों में शामिल हो सकते हैं।

ललित कला स्नातक मुख्यधारा के स्नातक

रोजगार और उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में प्रशिक्षण के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, बैंकिंग, आर्ट गैलरी, बीमा, मीडिया और जनसंपर्क।

उम्दा कलाकार विभिन्न प्रकार के मीडिया और तकनीकों का उपयोग करके कलाकृतियों का निर्माण करने का काम करते हैं।

आप अपने काम को संग्रहालयों, निजी दीर्घाओं में प्रदर्शित कर सकते हैं या निजी संग्रह रख सकते हैं और अपने काम के लिए पुरस्कृत हो सकते हैं। आपके द्वारा बनाई गई वस्तुएं स्टूडियो, नीलामी, स्टोर या कला और शिल्प शो में बिकेंगी।

फाइन आर्ट्स में स्कोप काफी अच्छा है, आप इस प्रोफेशनल करियर के तहत सम्मान और पैसा दोनों कमा सकते हैं। मल्टीमीडिया कलाकार और एनिमेटर मोशन पिक्चर या वीडियो गेमिंग उद्योगों में काम करते हैं।

प्रमुख जॉब प्रोफाइल इस प्रकार हैं:

- आर्ट थैरेपिस्ट
- मल्टीमीडिया प्रोग्रामर
- ड्राइंग टीचर
- प्रोडक्शन आर्टिस्ट
- रचनात्मक निर्देशक
- फर्नीचर डिजाइनर
- 3डी कलाकार
- सेट डिजाइनर
- यूजिक टीचर
- संपादक
- कला निर्देशक
- एनिमेटर

रोजगार के क्षेत्र:

- विज्ञापन कंपनियां
- कला स्टूडियो
- सिलाई की दुकानें
- शिक्षा संस्थान
- टेलीविजन उद्योग
- एनीमेशन
- वस्त्र उद्योग
- बुटीक
- थियेटर
- फैशन हाउस
- शिक्षण
- स्कल्पचर

सैलरी पैकेज

वेतन नौकरियों के आधार पर अलग-अलग होते हैं। ललित कला में स्नातक 2 से 3 लाख रुपये प्रति वर्ष के बीच कमा सकता है। हालांकि यह उनकी प्रतिभा के आधार पर निर्भर करता है। अनुभव और ज्ञान के साथ-साथ सैलरी पैकेज में भी बढ़ोतरी होती रहती है। जो लोग विज्ञापन एजेंसियों और पब्लिशिंग हाउसों में काम करना चाहते हैं, वे लगभग 4 से 5 लाख रुपये प्रति वर्ष का आकर्षक वेतन कमा सकते हैं।

बनाई जाती है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री को मुख्य तौर पर दो भागों में बांट कर देख सकते हैं- अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सेक्टर। अपस्ट्रीम सेक्टर में खोज, उत्पादन व तेल और प्राकृतिक गैसों का दोहन कैसे किया जाए, इसकी शिक्षा व ट्रेनिंग दी जाती है। डाउनस्ट्रीम सेक्टर में रिफाइनिंग, मार्केटिंग और वितरण से संबंधित पूरी जानकारी दी जाती है। पेट्रोलियम के क्षेत्र में टीम की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। एक पेट्रोलियम इंजीनियर को जियोलॉजिस्ट, अन्वेषणकर्ता, इंजीनियर, पर्यावरण क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ काम करना पड़ता है।

अवसर

पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नौकरी की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। लगभग आठ लाख लोगों को रोजगार देने वाला यह क्षेत्र अवसरों से भरा पड़ा है। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस, ओएनजीसी, पेट्रोनेट जैसी नामी-गिरामी कंपनियों के द्वारा आपके लिए खुले हैं। जिस तरह पेट्रोल के नए भंडार और क्षेत्र मिल रहे हैं, उससे यह क्षेत्र आने वाले समय में बड़ा लाभकारी साबित होगा।



घर बैठे इसरो से करें फ्री ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शैक्षिक संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए कई फ्री पाठ्यक्रम प्रदान किए हैं। पूरा करने पर सर्टिफिकेट दिया जाता है।

रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में प्रोफेशनल के नॉलेज एंड स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए इसरो द्वारा फ्री ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की गई है। यह ऑनलाइन कोर्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के तहत भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान (आईआईआरएस) द्वारा प्रदान किया जा रहा है। आईआईआरएस की ओर से शुरू एडवांस इन रिमोट सेंसिंग टैक्निकल फॉर जियोलॉजिकल एप्लीकेशन कोर्स प्रोफेशनल को रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में प्रैक्टिकल विशेषज्ञता को हासिल करने के मकसद से डिजाइन किया गया है। रिमोट सेंसिंग फॉर जियोलॉजिकल कोर्स अनेक एप्लीकेशन से संबंधित है, जिसमें मैपिंग, मॉनिटरिंग आदि पहलू शामिल हैं।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शैक्षिक संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए कई फ्री पाठ्यक्रम प्रदान किए हैं। इन पाठ्यक्रमों को पूरा करने के बाद, सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये पाठ्यक्रम कई विषयों पर आधारित हैं और उन्हें अपने करियर में इस्तेमाल किया जा सकता है।

कोर्स में शामिल हैं ये विषय

भूविज्ञान में रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के मूलभूत सिद्धांत, जिसमें ऑप्टिकल थर्मल, माइक्रोवेव, हाइपरस्पेक्ट्रल आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त भू-वैज्ञानिक विज्ञान में रिमोट सेंसिंग की भूमिका, लैंडस्काइड, मैपिंग और मॉडलिंग जीएनएसएस, जियोडेसी और जियोफिजिक्स का एकीकरण और ग्रहों की खोज आदि विषय रिमोट सेंसिंग पाठ्यक्रम में शामिल हैं।

कौन है आवेदन के लिए पात्र

एडवांस इन रिमोट सेंसिंग टैक्निकल फॉर जियोलॉजिकल एप्लीकेशन फ्री ऑनलाइन कोर्स के लिए अर्थ साइंस में स्नातकोत्तर छात्र व उसके समकक्ष विषय जैसे जियोलॉजी, एप्लाइड जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, अर्थ साइंस, जियो एक्सप्लोरेशन, जियोग्राफी आदि विषय और सिविल इंजीनियरिंग, जियोसाइंस, माइनिंग इंजीनियरिंग में बीटेक छात्र इस कोर्स में आवेदन करने के पात्र हैं।

कोर्स स्टडी मैटेरियल

ई-वलास प्लेटफॉर्म के जरिये पेशेवरों को लेकर स्लाइड, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर आदि स्टडी मैटेरियल प्रदान किए जाएंगे। सर्टिफिकेट दिया जाएगा नोडल सेंटर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने वाले छात्रों को 70 फीसदी उपस्थिति के आधार पर प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से पंजीकरण किया है, उन छात्रों को पाठ्यक्रम के प्रत्येक सत्र में 70 फीसदी घंटे उपस्थित होना होगा। व्यक्तिगत रूप से पंजीकरण करने वाले छात्र इसरो एलएमएस के माध्यम से ऑनलाइन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं।

ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स के फायदे

- ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स सुविधाजनक होते हैं और घर से आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं।
- आपको किसी विशेष स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे समय और प्रयास दोनों की बचत होती है।
- ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स आपको अपने नॉलेज एंड स्किल्स को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
- ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स आपको नई चीजें सीखने और अपने नॉलेज का विस्तार करने में मदद कर सकते हैं।
- ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स आपको अपने नेटवर्क का विस्तार करने और नए लोगों से मिलने में मदद कर सकते हैं।
- इसके साथ ही आप दुनिया भर के विशेषज्ञों से अपने पसंदीदा विषय सीख सकते हैं।



ऊर्जा का अहम स्रोत होने के नाते पेट्रोलियम की उपयोगिता से सभी वाकिफ हैं। भारत पेट्रोलियम पदार्थों की अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेश से आयात करता है। अगर आकड़ों की मानें तो पेट्रोलियम पदार्थों के उपयोग में भारत विश्व का आठवां बड़ा देश है। एचपीसीएल, बीपीसीएल, रिलायंस, इंडियन ऑयल जैसी कंपनियों से सरकार को भारी-भरकम राजस्व मिलता है।

अवसरों से भरा पड़ा है पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी का क्षेत्र

पहले इस क्षेत्र में जियोलॉजिस्ट की काफी मांग थी, समय बदलने के साथ मैकेनिकल क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इस इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाई। करियर की अनेक संभावनाओं को देखते हुए इस क्षेत्र में प्रबंधन से लेकर इंजीनियरिंग तक के कोर्स शुरू हुए हैं।

कोर्स

पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी ने बीबीए, एमबीए, एमटेक, बीटेक, एमएससी जैसे कोर्स शुरू किए हैं। इसके अलावा देश के चुनिदा संस्थानों ने पेट्रोलियम के क्षेत्र में बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमएससी और बीएससी जैसे कोर्स शुरू किए हैं। ये सभी कोर्स पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोटेक्नोलॉजी, गैस इंजीनियरिंग, पेट्रोमार्केटिंग आदि में शुरू किए हैं।

योग्यता

बारहवीं की परीक्षा भौतिक विज्ञान, गणित और रसायन विज्ञान से 50 प्रतिशत अंकों से पास करने के बाद आप इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। कैमिकल और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में बीई और बीटेक कर चुके छात्र पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में एमटेक के लिए आवेदन कर सकते हैं। बीबीए में प्रवेश के लिए बारहवीं किसी भी संकाय से उत्तीर्ण होना जरूरी है।

स्टडी कोर्स

पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में छात्र जियोलॉजी, भौतिकी और इंजीनियरिंग के सिद्धांतों द्वारा पेट्रोलियम की रिकवरी, डेवलपमेंट और प्रोसेसिंग के बारे में जानते हैं। इसके अलावा ड्रिलिंग, मैकेनिक्स, पर्यावरण संरक्षण और पेट्रोलियम जैसे विषयों पर छात्रों की पकड़

संक्षिप्त समाचार

आप से भाजपा में शामिल करतार सिंह तंवर ने गंवाई विधायकी, विधानसभा स्पीकर का ऐवशन



नई दिल्ली, एजेंसी। आम आदमी पार्टी से भाजपा में शामिल हुए छतरपुर के विधायक करतार सिंह तंवर की विधायकी गंवायी पड़ी है। दिल्ली एसेंबली स्पीकर राम निवास गोयल ने दलबदल विरोधी कानून के तहत करतार सिंह तंवर की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से आप के टिकट पर विधायक चुने गए तंवर ने इस साल जुलाई में आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी। दिल्ली विधानसभा सचिवालय की ओर से मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि स्पीकर राम निवास गोयल ने करतार सिंह तंवर को अयोग्य घोषित कर दिया है। उनकी विधानसभा सदस्यता 10 जुलाई, 2024 से समाप्त कर दी गई है। उनके खिलाफ कार्रवाई दलबदल विरोधी कानून के तहत की गई है। आम आदमी पार्टी को छोड़ने के बाद करतार सिंह तंवर एक अन्य विधायक राज कुमार आनंद के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। पटेल नगर आरक्षित सीट से विधायक राज कुमार आनंद ने अप्रैल में केजरीवाल सरकार में समाज कल्याण मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और पार्टी भी छोड़ दी थी। उनको भी स्पीकर ने विधायक के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया था। 10 जुलाई को भाजपा में शामिल होने के बाद करतार सिंह तंवर ने विकास कार्यों के उप पड़ने का दावा करते हुए कहा था कि पानी और स्वच्छता से जुड़ी समस्याओं के कारण दिल्ली नरक में बदल गई है। दिल्ली की हालत खराब है। एक पार्टी जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के आंदोलन से निकली वह करणन में डूब चुकी है। भाजपा की दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की मौजूदगी में करतार सिंह तंवर और राज कुमार आनंद ने भाजपा का दामन थामा था।

एयर ट्रेन से जुड़ेंगे आईजीआई के तीनों टर्मिनल



नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली हवाई अड्डे पर एक से दूसरे टर्मिनल तक आने-जाने के लिए यात्रियों को एयर ट्रेन की सुविधा मिलेगी। एयर ट्रेन एयरोसिटी और कार्गो तक भी जाएगी। इसके लिए डायल की तरफ से टेंडर जारी किया गया है। वर्ष 2027 तक कार्य पूरा होना का लक्ष्य रखा गया है। जानकारी के अनुसार, दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल-2 और 3 एक जगह हैं, जबकि टर्मिनल-1 कुछ दूरी पर है। इन टर्मिनल के बीच सफर करने के लिए अभी यात्रियों को डीटीसी बस का इंतजार करना पड़ता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर औसतन सात करोड़ से ज्यादा यात्री प्रत्येक वर्ष सफर करते हैं। आने वाले वर्षों में यह आंकड़ा 10 करोड़ से ज्यादा पहुंचने का अनुमान है। एयरपोर्ट पर यात्रियों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए संचालन कंपनी डायल भविष्य की तैयारी कर रही है। तीनों टर्मिनल को आपस में जोड़ने के लिए डायल ने एयर ट्रेन चलाने का फैसला किया है। सूत्रों ने बताया कि एयर ट्रेन के कुल चार उद्घाटन होंगे। यह टर्मिनल-1, टर्मिनल-2-3, एयरोसिटी और कार्गो सिटी पर रुकेगी। कुल 7.7 किलोमीटर चलने वाली यह एयर ट्रेन यात्रियों के लिए बेहद सुविधाजनक होगी। इसमें यात्रियों का समय बचेगा। देश में चलने वाली यह पहली एयर ट्रेन भी होगी। डायल की तरफ से इसे लेकर टेंडर निकाला गया है। इसके साथ ही मंत्रालय को भी जानकारी दी गई है।

प्लॉट बचाने को साथ रह रहे आठ दंपतियों ने लिया कागजी तलाक, यीडा की गोपनीय जांच में खुलासा

नई दिल्ली, एजेंसी। यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) के औद्योगिक प्लॉट के आवंटन के बाद आठ दंपतियों ने तलाक के दस्तावेज पेश कर दिए, जबकि वे साथ रह रहे हैं। प्राधिकरण की जांच में इसका खुलासा हुआ है। योजना में पति-पत्नी दोनों को प्लॉटों के आवंटन का नियम नहीं था।

यमुना प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2015 से लेकर अब तक निकाली गई औद्योगिक भूखंडों की योजना की जांच करने पर सामने आया कि 47 प्लॉटों का आवंटन पति-पत्नी दोनों के नाम पर हुआ। जब इन मामलों की जांच कर किसी एक को प्लॉट सरेंजर करने के लिए कहा गया तो कुछ दिन के बाद ही आठ दंपतियों ने तलाक के कागज लगा दिए। इसके अलावा उन्होंने कंपनी और फर्म आदि अलग-अलग होने के दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए। प्राधिकरण का दावा है कि गोपनीय जांच में सामने



आया है कि पति-पत्नी दोनों साथ में ही रह रहे हैं। प्लॉट पाने के लिए कागजी तलाक ले लिया है ताकि दोनों का प्लॉट आवंटन बना रहे। एमएसएमई स्कीम के तहत आवंटित हुए सभी भूखंड चार हजार वर्गमीटर से छोटे हैं। यमुना प्राधिकरण की जांच में सामने आया है

कि कुल 47 में से 32 प्लॉटों के आवंटन 10 परिवारों के नाम पर ही हैं। 16 भूखंडों का आवंटन अलग-अलग तरह की कंपनियों और फर्म के नाम पर मिला है। जांच के बाद एक आवंटनी प्लॉट सरेंजर भी कर दिया। एसीओ की अध्यक्षता में गठित जांच कमेटी की

रिपोर्ट को आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। बोर्ड के संज्ञान में लाने के बाद इन पर फेसला लिया जाएगा कि इनका आवंटन बरकरार रहेगा या निरस्त किया जाना है। बहरहाल इन मामलों के सामने आने के बाद प्राधिकरण की हाल में शुरू हुई 361 आवासीय भूखंडों की योजना में भी इस तरह के मामलों की जांच में सख्ती बढ़ा दी गई है। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह का कहना है कि भूखंड आवंटन के सभी 47 मामलों को बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। इन मामलों में क्या कार्रवाई होनी है, यह बोर्ड ही तय करेगा।

दंपति की चट्टा (बदला हुआ नाम) नाम की कंपनी है। एमएसएमई स्कीम के भूखंड में पुरुष ने चट्टा और महिला ने चट्टा एंड संस के नाम से आवेदन किया। इन दोनों को ही डॉ. अरुणवीर सिंह को भूखंड आवंटित हो गया, लेकिन पति-पत्नी दोनों को भूखंड आवंटन का नियम नहीं है।



मुझे उम्मीद है आप जवाब देंगे; केजरीवाल का मोहन भागवत को लेटर

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत को लेटर लिखा है। उन्होंने पीएम मोदी की रिटायरमेंट समेत 5 मुद्दों पर उत्तर जवाब देने की अपील की है। केजरीवाल ने लेटर में कहा है कि उन्होंने लेटर राजनीतिक दल के नेता की हैसियत से नहीं बल्कि सामान्य नागरिक तौर पर लिखा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भागवत जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि वह देश के हालात को लेकर चिंतित हैं। केजरीवाल ने लिखा, जिस दिशा में बीजेपी की केंद्र सरकार देश और देश की राजनीति को ले जा रही है, यह पूरे देश के लिए हानिकारक है। अगर यही चलता रहा तो हमारा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, हमारा देश खत्म हो जाएगा। पार्टियां तो आती-जाती रहेंगी, चुनाव आते-जाते रहेंगे, नेता आते-जाते रहेंगे, लेकिन भारत देश हमेशा रहेगा। इस देश का तिरंगा आसमान में गर्व से हमेशा लहराए।

दिल्ली की सड़कों पर नहीं लगेगा जाम

नई दिल्ली, एजेंसी। राजधानी दिल्ली में जाम को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस एवं डीटीसी अधिकारी संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। इसके लिए दोनों विभागों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। ट्रैफिक पुलिस ग्रुप में बस की खराबी को लेकर पूरी जानकारी साझा करती है और डीटीसी अधिकारी तुरंत संज्ञान लेकर बस को ठीक करवाते हैं। पहले जहां इस कार्य में 60 से 90 मिनट तक लगते थे, अब 25 से 30 मिनट में हो जाता है। दिल्ली में जाम लगने के प्रमुख कारणों में सड़क पर बसों की खराबी शामिल है। औसतन 100 बसें (डीटीसी और क्लस्टर) रोजाना खराब होती हैं। बस खराब होने के बाद उस डिपो को सूचित किया जाता था, जहां की वह बस है। फिर वहां से मैकेनिक आकर इसे ठीक करता था, तब जाकर बस को सड़क से हटाया जाता था। इस दौरान हजारों वाहन चालकों को लंबे समय का सामना करना पड़ता था। ट्रैफिक पुलिस के विशेष आयुक्त अजय चौधरी ने बताया कि उन्होंने डीटीसी की एमडी शिल्पा शिंदे से इस समस्या को लेकर चर्चा की।

वो हमले करते रहेंगे... सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने स्वाति मालीवाल को टिप्स दी

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार को जमानत दे दी। उनपर सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोप थे। इस दौरान शीर्ष न्यायालय ने सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग को लेकर भी अहम टिप्पणी की है। अदालत ने बताया है कि वह भी ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करते हैं और उससे कैसे निपटते हैं।

सोमवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। अदालत ने कुमार को मालीवाल के साथ मारपीट मामले में बेल दे दी है। सुनवाई के दौरान जब मालीवाल के वकील ने अदालत को बताया है कि मारपीट पर ही अपराध खत्म नहीं हुआ था और ये सोशल मीडिया पर भी अब तक जारी है। उन्होंने कहा, याचिकाकर्ता और उनके समर्थक मुझे झूठे और हर जगह ट्रोल कर रहे हैं। इसपर



कुमार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, क्या मैं सोशल मीडिया को कंट्रोल करता हूँ? लॉर्डशिप जानते हैं कि कैसे हमें और न्यायाधीशों को ट्रोल किया जाता है। जस्टिस भुइयां ने कहा, ट्रोलिंग दुर्भाग्यपूर्ण है। जब हम एक के पक्ष में फैसला सुनाते हैं, तो दूसरे पक्ष की तरफ से हमें भी ट्रोल किया जाता है। जस्टिस कांत ने कहा, गैर जिम्मेदार लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, जिसे अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी नहीं है। वे हमला करना

है, इसलिए कुमार की रिहाई से जांच पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुमार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 12 जुलाई के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। कुमार की तरफ से गवाहों को प्रभावित करने की संभावना के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए, पीठ ने उन्हें कई शर्तों के साथ जमानत दी। पीठ ने निर्देश दिया कि कुमार को केजरीवाल के निजी सहायक के रूप में बहाल नहीं किया जाएगा और न ही मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई आधिकारिक कार्यभार दिया जाएगा। न्यायालय ने सभी गवाहों से पूछताछ पूरी होने तक कुमार के मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश पर भी रोक लगा दी। उच्चतम न्यायालय ने कहा, 'जमानत निचली अदालत द्वारा लगाई जाने वाली अन्य शर्तों के अधीन होगी।' कुमार ने 13 मई को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर मालीवाल पर कथित तौर पर हमला किया था।

बांग्लादेश के बाहर नहीं पसंद आए मुहम्मद यूनुस, न्यूयॉर्क में लगे वापस जाओ के लगे नारे; प्रदर्शनकारी बोले- हसीना हमारी पीएम

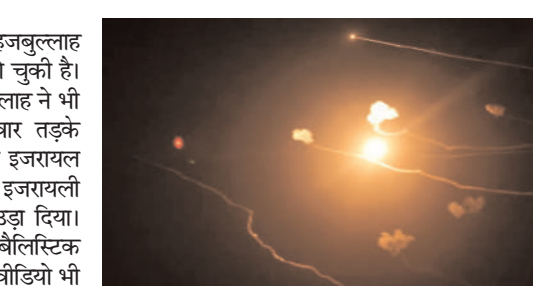
न्यूयॉर्क, एजेंसी। 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंचे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मुहम्मद यूनुस को सोमवार देर रात न्यूयॉर्क में अपने होटल के बाहर विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। न्यूयॉर्क में आधिकारिक होटल में उनके आगमन से पहले प्रदर्शनकारियों ने मुहम्मद यूनुस के खिलाफ वापस जाओ के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भी यूनुस के खिलाफ नारेबाजी की।

भारतीय मीडिया दल ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की तो उन्होंने उनका जवाब देने से भी परहेज किया। प्रसारित वीडियो में यूनुस के सुरक्षाकर्मी पत्रकारों को दूर रखने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए कि यूनुस वापस जाओ, पद छोड़ो। वह हाथों में बैनर थामे हुए थे जिन पर लिखा था कि शेख हसीना हमारी प्रधानमंत्री हैं।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि 84 वर्षीय यूनुस ने असंवैधानिक, अवैध रूप से बांग्लादेश की सत्ता हासिल की। उन्होंने गंदी राजनीति के साथ सत्ता पर कब्जा किया और बहुत से लोग बेवजह मारे गए। एक प्रदर्शनकारी शेख जमाल ने कहा कि अभी तक हमारी निर्वाचित प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा नहीं दिया है। हम संयुक्त राष्ट्र से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि यूनुस ने यहां बांग्लादेशी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं किया है। उन्हें वापस भेजा जाए। एक अन्य प्रदर्शनकारी डीएम रोनाल्ड ने कहा कि हम शांति चाहते हैं। हम धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। बलपूर्वक सत्ता हासिल करने के बाद उन्होंने हिंदुओं और ईसाइयों को मारना शुरू कर दिया है। उधर, बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू देश के नागरिक हैं और अंतरिम सरकार देश में नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भी हिंसा हुई है, उसे हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के रूप में दिखाया जा रहा है, यह सही नहीं है।

अब हिजबुल्लाह ने एक साथ छोड़ी मिसाइलें और ड्रोन, इजरायल ने हवा में ही उड़ा; 40 शहरों में बजे सायरन

येरूशालम, एजेंसी। इजरायल और हिजबुल्लाह आतंकियों के बीच महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी है। इजरायल के भीषण अटैक के बाद हिजबुल्लाह ने भी काउंटर अटैक शुरू कर दिया है। बुधवार तड़के साउथ लेबनान से कई मिसाइलें और ड्रोन इजरायल की तरफ दागे गए। हालांकि अधिकांश को इजरायली रक्षा प्रणाली आयरन डोम ने हवा में ही उड़ा दिया। इसमें तेल अवीव की तरफ आती एक बैलिस्टिक मिसाइल भी थी। इजरायली सेना ने इसका वीडियो भी शेयर किया है। हिजबुल्लाह के अचानक हमले से तेल अवीव समेत 40 शहरों में सायरन बजे। गाजा में हाहाकार मचाने के बाद अब इजरायली सेना लेबनान में कहर बनकर टूट पड़ी है। पहले ही एक हवाई हमले में सैकड़ों को मौत के घाट उतारने के बाद इजरायली सेना दूसरे बड़े हमले की तैयारी कर रही है। इजरायली सेना का कहना है कि लेबनान में उसे कम समय में अधिक लक्ष्य हासिल करने हैं, इसलिए सेना अधिक घातक हमले कर रही है। पहले अटैक में आईडीएफ ने 1600 ठिकानों पर हमले किए और एक ही झटके में कई हिजबुल्लाह कमांडरों को मार डाला। इस हमले में निर्दोषों की भी जान चली गई। कुल 500 गैर जातों में 90 महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सेना का कहना है कि जल्द ही लेबनान पर दूसरा बड़ा अटैक होने वाला है।



इस बीच हिजबुल्लाह ने भी इजरायल पर काउंटर अटैक शुरू कर दिया है। इजरायल को पहले ही अदृश था इसलिए देशभर में हफतेभर की इमरजेंसी जारी कर रखी थी। इजरायली सेना ने कहा कि बुधवार को इजरायल की आर्थिक राजधानी तेल अवीव समेत 40 शहरों में सायरन बजे। दरअसल, हिजबुल्लाह ने लेबनान से सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और कई ड्रोन से एक साथ अटैक कर दिया था। तेल अवीव पर साउथ लेबनान से दागी गई मिसाइल को आयरन डोम ने हवा में ही उड़ा दिया। इजरायली सेना का कहना है कि हमले में किसी के भी हताहत की सूचना नहीं है। इसके अलावा किसी तरह के बड़े नुकसान की भी सूचना नहीं है। सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह के हमले से पूरे मध्य इजरायल में सायरन बजे।

पाकिस्तानी भिखारियों से सऊदी अरब परेशान

शहबाज सरकार से इन पर रोक लगाने को कहा

इस्लामाबाद, एजेंसी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से आने वाले भिखारियों की बढ़ती संख्या को लेकर शहबाज सरकार को चेतावनी दी है। पाकिस्तान से हर साल बड़ी संख्या में लोग उमराह वीजा (तीर्थयात्रा वीजा) पर सऊदी अरब जाते हैं और वहां भीख मांगने लग जाते हैं। पाकिस्तानी वेबसाइट द ट्रिब्यून एक्सप्रेस के मुताबिक सऊदी हज मंत्रालय ने पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय से कहा है कि वे इस पर जल्द रोक लगाएं। मंत्रालय ने कहा कि अगर पाकिस्तान सरकार ऐसा नहीं करती है तो इसका असर पाकिस्तानी उमराह और हज यात्रियों पर पड़ सकता है। उमराह एक्ट लागू करके, ट्रैवल एजेंसियों पर सख्ती बरती जाएगी रिपोर्ट के मुताबिक भिखारियों को सऊदी भेजने से रोकने के लिए



पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने 'उमराह एक्ट' लाने करने का फैसला किया है। इसका मकसद उमराह वीजा दिलाने में मदद करने वाली ट्रैवल एजेंसियों को रेग्युलेट करना और उन्हें कानूनी

नियंत्रण के तहत लाना है। इससे पहले मंगलवार को सऊदी राजदूत नवाफ बिन सैद अहमद अल-मलिकी और पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी के बीच मुलाकात हुई थी। इसमें नकवी ने राजदूत को यकीन

दिलाया था कि सरकार सऊदी अरब में भिखारियों को भेजने के लिए जिम्मेदार माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्री नकवी का मानना है कि ऐसी घटना पाकिस्तान की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। इस पर नकेल कसने के लिए अब संघीय जांच एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने ही कराची एयरपोर्ट पर 11 लोगों को पकड़ा गया था। ये सऊदी जा रही एक फ्लाइट में बैठने की तैयारी में थे। पूछताछ में पता चला कि उनका मकसद वहां जाकर भीख मांगना था। फ्लाइट में सवार 16 लोगों को प्लेन से उतारा गया था और गिरफ्तार किया गया था। ये भी वहां भीख मांगने जा रहे थे। पिछले साल भी सऊदी अरब ने की थी शिकायत पिछले साल सितंबर में ओवरसीज अधिकारियों की मीटिंग में सऊदी अरब ने पाकिस्तान से हज का कोटा देने में सावधानी बरतने को कहा था।

सिक लीव नहीं मिली तो काम पर लौटी महिला, इ्यूटी के दौरान हो गई मौत

सुखोथाई, एजेंसी। महिला कर्मचारी ने एक दिन की सिक लीव लेनी चाही लेकिन, उसके मैनेजर को लगा कि वह बहाना बना रही है। इसलिए उसे छुट्टी नहीं दी। महिला काम पर आई लेकिन, इ्यूटी के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला थाईलैंड के सुखोथाई प्रांत का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार, महिला काम के दौरान बेहोश हो गई थी और बाद में उसकी मौत हो गई। महिला कर्मचारी की मौत का मामला अब तूल पकड़ रहा है। सोशल मीडिया पर महिला को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। कंपनी पर कर्मचारियों के शोषण की कहानियां शेयर की जा रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार, सुखोथाई प्रांत की 30 वर्षीय महिला जिसकी पहचान केवल में के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि महिला समुत प्राकान प्रांत के मुआंग जिले में बंग पु औद्योगिक एस्टेट में एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में कर्मचारी थीं। फेसबुक पेज पर महिला के सहकर्मियों ने गुप चैट के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। जिसमें दावा किया गया है कि कंपनी के मैनेजर ने उसे सिक लीव के लिए छुट्टी नहीं दी। जब महिला ने अपनी परेशानी बताई तो मैनेजर ने उसे मेडिकल सर्टिफिकेट लाने को कहा था। बीमारी में काम के दौरान उसकी मौत हो गई।